वर्ष: 2 अंक: 10

16-30 नवंबर, 2021 (नि:शुल्क)

न्यू इंडिया समाचार

सुरक्षित महिला राष्ट्र की शक्ति

नए भारत की नारी शक्ति को सुरक्षा के साथ लैंगिक न्याय व समानता के अवसर अब बन रहे हैं राष्ट्र की समृद्धि का आधार।

"100 करोड़ वैक्सीन डोज के बाद भारत नए उत्साह और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है"

वैक्सीनेशन में 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने के बाद निर्धारित 'मन की बात' प्रोग्राम में इसका जिक्र स्वाभाविक था। 'सबका प्रयास' किस तरह सफलता का आधार बना, इसका जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्गम इलाकों में जाकर टीका लगाने वाली हेल्थ वर्कर से भी संवाद किया। साथ ही, भगवान बिरसा मुंडा को याद कर युवाओं को स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में आदिवासियों के योगदान के बारे में पढ़ने का आह्वान, स्वच्छाग्रहियों के उदाहरण से स्वच्छता को सदैव आदत बनाने और नारी शक्ति की राष्ट्र सुरक्षा में योगदान सहित अन्य विषयों पर भी विचार रखे। पेश हैं 'मन की बात' के अंश:

- **वैक्सीन:** 100 करोड़ वैक्सीन डोज के बाद आज देश नए उत्साह, नई ऊर्जा से आगे बढ़ रहा है। हमारे वैक्सीन कार्यक्रम की सफलता, भारत के सामर्थ्य और सबके प्रयास के मंत्र की शक्ति को दिखाती है।
- **पारंपरिक चिकित्सा का वैश्विक केंद्र:** भारत पारंपरिक चिकित्सा के बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। भारत गरीबी उन्मूलन, जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। योग और आयुष को लोकप्रिय बनाने के लिए डब्लूएचओ के साथ मिलकर काम कर रहा है। डब्लूएचओ भारत में पारंपरिक चिकित्सा के लिए वैश्विक केंद्र स्थापित करेगा।
- **अटल प्रेरणा:** 1977 में अटल जी ने संयुक्त राष्ट्र को हिंदी में संबोधित कर इतिहास रच दिया था। अटल जी ने कहा था- "यहां मैं राष्ट्रों की सत्ता और महत्ता के बारे में नहीं सोच रहा हूं। आम आदमी की प्रतिष्ठा और प्रगति मेरे लिए कहीं अधिक महत्व रखती है। अंततः हमारी सफलताएं और असफलताएं केवल एक ही मापदंड से नापी जानी चाहिए कि क्या हम पूरे मानव समाज, वस्तुतः हर नर-नारी और बालक के लिए न्याय और गरिमा की आश्वस्ति देने में प्रयत्नशील हैं।" अटल जी की ये बातें हमें आज भी दिशा दिखाती हैं।
- **सशक्त नारी:** हंसा मेहता और लक्ष्मी मेनन जैसी महिलाओं ने संयुक्त राष्ट्र में लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण की अवधारणा पेश की। 1953 में विजया लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनीं। पिछले कुछ वर्षों में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या दोगुनी हो गई है। 2014 में जहां इनकी संख्या 1.05 लाख के करीब थी, वहीं 2020 में यह बढ़कर 2.15 लाख हो गई है। कई बेटियां सबसे कठिन प्रशिक्षणों में से एक विशेष जंगल युद्ध कमांडों की ट्रेनिंग ले रही हैं और जल्द ही वे हमारी कोबरा बटालियन का हिस्सा होंगी।
- **नई ड्रोन नीति:** भारत की नई ड्रोन तकनीक का उपयोग कोविड-19 वैक्सीन आपूर्ति और कृषि में किया जा रहा है। भारत बड़े पैमाने पर परिवहन उद्देश्यों के लिए ड्रोन का उपयोग करने पर काम कर रहा है। आपात स्थिति के दौरान सहायता प्रदान करने तथा कानून-व्यवस्था और बड़ी ढांचागत परियोजनाओं की निगरानी करने में मदद कर रहा है। नई ड्रोन नीति के बाद विदेशी और घरेलू निवेशक कई ड्रोन स्टार्ट-अप में निवेश कर विनिर्माण इकाइयां स्थापित कर रही हैं।
- **अमृत महोत्सव में नई पहल:** संगीत, कला और गीतों के जरिए भारत को अमृत महोत्सव से जोड़ने के लिए सरदार पटेल की जयंती 31 अक्टूबर से तीन प्रतियोगिताएं शुरू होने जा रही हैं। देशभक्ति गीतों पर प्रतियोगिता, रंगोली की कला से जुड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता और कला को पुनर्जीवित करने के लिए देशभक्ति से संबंधित लोरी लिखने की प्रतियोगिता।

'मन की बात' पूरी सुनने के लिए QR कोड Scan करें

न्यू इंडिया
समाचार
वर्ष: 02, अंक: 10 | 16-30 नवंबर, 2021

संपादक
जयदीप भटनागर,
प्रधान महानिदेशक,
पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली

वरिष्ठ सलाहकार संपादक
संतोष कुमार

वरिष्ठ सहायक सलाहकार संपादक
विभोर शर्मा
सहायक सलाहकार संपादक
चन्दन कुमार चौधरी

भाषा संपादन
सुमित कुमार (अंग्रेजी), अनिल पटेल (गुजराती), नदीम अहमद (उर्दू), शोणित कुमार गोस्वामी (असमिया), विनया पी.एस. (मलयालम), पॉलमी रक्षित (बंगाली), हरिहर पंडा (ओड़िया)

सीनियर डिजाइनर
श्याम शंकर तिवारी
रविन्द्र कुमार शर्मा
डिजाइनर
दिव्या तलवार, अभय गुप्ता

प्रकाशक और मुद्रकः
सत्येन्द्र प्रकाश,
प्रधान महानिदेशक, बीओसी
(ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन)

मुद्रणः जेके ऑफसेट ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड, बी-278, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020

पत्राचार और ईमेल के लिए पताः
कमरा संख्या-278,
ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन, सूचना भवन, द्वितीय तल, नई दिल्ली- 110003
ईमेल- **response-nis@pib.gov.in**

आर. एन. आई. नंबर
DELHIN/2020/78812

अंदर के पन्नों पर...

सुरक्षित महिला समृद्ध राष्ट्र की शक्ति

आवरण कथा
तीन तलाक समेत महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए सख्त कानून बनाकर सुरक्षित महिला, समृद्ध राष्ट्र का संदेश देता भारत। पेज 10-19

कुप्रथाओं की जंजीर तोड़ महिलाओं-वंचितों को मुख्यधारा में लाए ज्योतिबा फुले
छुआछूत, बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं के विरोध में आवाज उठाकर महिला शिक्षा के लिए जीवन अर्पण करने वाले ज्योतिबा को नमन। पेज 6-7

उत्तर प्रदेश को सेहत के साथ उड़ान का डबल डोज

9 नए मेडिकल कॉलेज के साथ पूर्वांचल बनेगा उत्तर प्रदेश का मेडिकल हब तो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ देश के पर्यटन मानचित्र पर अहम लकीर खींचेगा कुशीनगर। पेज 26-29

समाचार सार
पेज 4-5

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की नई उड़ान
रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आगे बढ़ता भारत। पेज 8-9

आसियान देशों के साथ मित्रता पर्व मनाएगा भारत
आसियान और द. एशिया शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पेज 25

अब 9 दिन चले अढ़ाई कोस नहीं, कहिए ढाई दिन में चले सौ कोस
कोविड से जंग में लगातार आगे बढ़ रहा भारत। पेज 30-33

आतंक को जवाब
गृहमंत्री अमित शाह का जम्मू-कश्मीर दौरा। पेज 34-35

अब आपके सिर पर अपनी छत
प्रधानमंत्री आवास योजना ने पूरा किया अपने घर का सपना। 36-38

राष्ट्र की प्रगति को मिली 'गति' की 'शक्ति'
कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले। पेज 39

रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के अवार्ड
67 वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का वितरण। पेज 40

संविधान की नींव में नारी सशक्तीकरण की आवाज
सातवें संविधान दिवस पर इस बार अमृत महोत्सव की श्रृंखला में पढ़िए उन महिला विभूतियों के बार में जिन्होंने न केवल स्वतंत्रता आंदोलन में योगदन दिया बल्कि संविधान बनाने में भी अहम भूमिका निभाई । पेज 20-24

संपादक की कलम से...

सादर नमस्कार,

"महिला- वो शक्ति है, सशक्त है, वो भारत की नारी है, न ज्यादा में, न कम में, वो सब में बराबर की अधिकारी है।"

किसी भी संस्कृति की प्रगति महिलाओं के सशक्तीकरण के बिना अधूरी है। आज नए भारत का मुद्दा महिलाओं के विकास का नहीं, बल्कि महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास का है। खेल कूद हो अथवा अंतरिक्ष विज्ञान, हमारे देश की महिलाएं किसी से पीछे नहीं हैं। आईएमएफ की रिपोर्ट बताती है कि महिलाओं को पुरुषों के समान सभी कार्यों में हिस्सेदारी मिले तो भारत की जीडीपी 27 फीसदी तक बढ़ सकती है। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी जरूरत है- महिलाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना। वर्तमान केंद्र सरकार ने इस महत्व को बखूबी समझा और तीन तलाक जैसी कुप्रथाओं पर कुठाराघात किया। बीते कुछ वर्षों में ही समाज ही नहीं, परिवार के भीतर भी महिलाओं और पुरुषों में भेदभाव को खत्म करने की पहल करते हुए सुरक्षा का भाव पनपने लगा है। इसी का परिणाम है कि केंद्र सरकार की अधिकांश योजनाओं की लाभार्थी अब महिलाएं हैं और महिला के नेतृत्व में विकास नीतिगत प्राथमिकता बन गई है।

महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए जागरूक करने के लिए संयुक्त राष्ट्र हर साल 25 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाता है, ऐसे में महिला शक्ति के लिए नए भारत में नए अवसर के साथ सुरक्षा का माहौल किस तरह उपलब्ध कराया जा रहा है, यही इस बार की आवरण कथा बनी है। महिला सुरक्षा के लिए सरकार के साथ-साथ सभ्य समाज की सोच भी महत्वपूर्ण कड़ी है और इसमें 'सबका प्रयास' राष्ट्र की प्रगति का आधार बन रहा है।

इसी सोच से भारत 100 करोड़ वैक्सीन डोज का रिकॉर्ड बना नए उत्साह और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। कोविड से आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में टीकाकरण की अभूतपूर्व गति ने परिवार, समाज और राष्ट्र को सुरक्षित माहौल दिया है। इसमें भी नारी शक्ति का योगदान महत्वपूर्ण है। नारी शक्ति के लिए शिक्षा की महत्ता महात्मा ज्योतिबा फुले से बेहतर कौन बता सकता है। उनकी पुण्यतिथि 28 नवंबर पर विशेष सामग्री इस अंक में है।

प्रधानमंत्री आवास योजना किस तरह महिलाओं को आवास के साथ-साथ मालिकाना हक दिला रही है, इस अंक में फ्लैगशिप योजना के रूप में शामिल है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के साथ-साथ अमृत महोत्सव की कड़ी में संविधान दिवस और संविधान बनाने में योगदान देने वालीं नायिकाओं को नमन इस बार के अंक का विशिष्ट आकर्षण है।

कोविड के खिलाफ युद्ध में सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते रहें।

पता- ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन,
सूचना भवन, द्वितीय तल
नई दिल्ली- 110003
ईमेल- **response-nis@pib.gov.in**

(जयदीप भटनागर)

आपकी बात...

न्यू इंडिया समाचार पत्रिका पढ़ने का मौका मिला। 'सबका प्रयास नए भारत का संकल्प' कवर पृष्ठ पर उल्लेखित पंक्तियां पूरे सितंबर अंक को सार्थक सिद्ध कर रही है। देश के बाहर - भीतर उपलब्धियों की जानकारी के साथ ही डिजिटल दुनिया, अन्न योजना, कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले, शिक्षा-सम्मान-सुरक्षा, टेलीविजन का इतिहास और सितंबर महीने में जन्म जयंती वाले महापुरुषों के बारे में जानकारी और गतिशक्ति आदि विशेष सामग्री से भरपूर अंक जानकारी परक और ज्ञानवर्धक है। विश्वसनीय जानकारी से प्रेरणा मिलती है।

भगवती प्रसाद गेहलोत
gehlotbp@gmail.com

न्यू इंडिया समाचार विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक सर्वश्रेष्ठ पत्रिका है। जब भी मुझे यह पत्रिका मिलती है तो मुझे बहुत खुशी होती है। मेरे परिवार में, हर कोई इस पत्रिका को पढ़ता है। हम इसे अपने मित्रों को भी भेजते हैं ताकि वे देश में हो रहे सर्वांगीण विकास से अवगत हो सकें।

पावनी गोयल
paavnigoyal04@gmail.com

अपने सुझाव हमें भेजें

पत्राचार और ईमेल के लिए पता:

कमरा संख्या-278,
ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन
सूचना भवन, द्वितीय तल
नई दिल्ली- 110003

ईमेल- **response-nis@pib.gov.in**

मुझे ईमेल के माध्यम से न्यू इंडिया समाचार प्राप्त हुई जिससे मैं भारत में हो रहे कई विकास कार्यों से अवगत हुआ। यह जानकारी सोशल मीडिया पर नहीं मिलती है। सरकार ने लगभग 100 करोड़ भारतीयों का टीकाकरण कराया है जिस पर मुझे गर्व है। यह पत्रिका विभिन्न विषयों पर विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। मुझे हर महीने इस पत्रिका को पढ़ना अच्छा लगता है।

perialwar.bhaskaran@gmail.com

मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूं और न्यू इंडिया समाचार पढ़ता हूं। इससे मुझे मेरी तैयारी में बहुत मदद मिलती है। यह सभी सरकारी योजनाओं पर उपयोगी जानकारी देने वाली पत्रिका है। लेख बहुत ही बेहतरीन और आसानी से समझ में आने वाले हैं।

जे पलानीवी
jpalanivel102@gmail.com

मुझे यह शानदार पत्रिका पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। इसके माध्यम से सरकार की सभी योजनाओं का पता चलता है। आधुनिक भारत में देश की विकास गाथा पढ़ कर गौरवान्वित महसूस करता हूं। अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा ।

सुनील चिलवाल
iamchilwal@gmail.com

परिवहन साधन की कमी से खेत-रास्ते में नहीं खराब होगी उपज, कृषि उड़ान 2.0 शुरुआत

वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य के साथ केंद्र सरकार ने जहां कृषि क्षेत्र में नई सहूलियतों की शुरुआत की है तो वहीं इससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर परिवहन तक की व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया है। एक वक्त था, जब खेतों में हुई पैदावार को बाजार तक पहुंचाने के लिए किसानों को बड़ी परेशानियों से जूझना होता था, लेकिन किसान रेल के साथ यह समस्या कम हुई तो केंद्र सरकार ने बीते वर्ष सितंबर में कृषि उड़ान योजना के साथ हवाई जहाज के जरिए दूरदराज के इलाकों तक सही समय में कृषि उत्पादों को पहुंचाने की शुरुआत की थी। अब इसी को और आगे बढ़ाते हुए कृषि उड़ान योजना 2.0 की शुरुआत की गई है। कृषि उड़ान योजना में जहां शुल्क वाले कुल भार में कृषि सामान का हिस्सा 50 प्रतिशत से अधिक होने पर हवाई कार्गो परिचालकों के लिए चुनिंदा भारतीय हवाई अड्डों पर पार्किंग शुल्क और 'टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग' शुल्क आदि से छूट दी जाती है तो वहीं अब कृषि उड़ान 2.0 में कृषि सामान का हिस्सा कुल भार में 50 प्रतिशत से कम होने पर भी चुनिंदा हवाईअड्डों पर हवाईअड्डा शुल्कों में पूर्ण रूप से छूट दी जाएगी। इससे परिवहन की लागतों में और कमी आएगी। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के अनुसार, कृषि उड़ान 2.0 में देश भर के 53 हवाई अड्डों पर मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और आदिवासी क्षेत्रों पर केंद्रित किया जाएगा। इस योजना के तहत 8 घरेलू और अंतरराष्ट्रीय व्यापार रूट्स की भी शुरुआत की जाएगी। इसमें बेबी कॉर्न की ढुलाई के लिए अमृतसर-दुबई, लीची के लिए दरभंगा को देश के अन्य एयरपोर्ट्स से और जैविक खाद्य उत्पादों के लिए सिक्कम से के लिए उड़ान शुरू की जायेगी। सरकार चेन्नई, विशाखापट्टनम और कोलकाता से पूर्वी एशियाई देशों को सी फूड्स भेजने के लिए उड़ान शुरू करेगी। दाल, फल एवं सब्जियों के लिए गुवाहाटी से हांगकांग के लिए व्यापारिक उड़ान की शुरुआत भी की जाएगी।

यूपीएससी: पिछड़ा वर्ग-ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवारों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) की श्रेणी से आने वाले सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले उम्मीदवारों को महत्वपूर्ण सुविधा प्रदान की है। यूपीएससी ने सरकारी सेवा की तैयारी कर रहे या भर्ती के लिए आवेदन करने वाले इन युवाओं की मदद के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर की शुरूआत की है। यह टोल फ्री नंबर है- 1800118711 , इसकी मदद से उम्मीदवार अपनी किसी भी समस्या से जुड़ी सहायता ले सकते हैं। देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के तहत शुरू की गई इस हेल्पलाइन के जरिए अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और दिव्यांग श्रेणी के ऐसे उम्मीदवार कर सकते हैं, जिन्हें यूपीएससी की किसी परीक्षा के लिए आवेदन करने में कोई कठिनाई आ रही हो।

ई-श्रम पोर्टल पर 4 करोड़ से ज्यादा कामगारों का रजिस्ट्रेशन, इसमें 50 फीसदी महिलाएं

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए शुरू किया गए ई-श्रम पोर्टल पर 2 महीनों में 4 करोड़ से अधिक लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इनमें से लगभग 50.02% लाभार्थी महिलाएं हैं और 49.98% पुरुष हैं। सबसे ज्यादा पंजीकरण के साथ ओडिशा, प. बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश सबसे आगे हैं। एक अनुमान के मुताबिक भारत में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या 38 करोड़ से ज्यादा है। यह विडंबना ही है कि जानकारी के अभाव में आजादी के 7 दशक बाद तक केंद्र सरकारी सामाजिक व सुरक्षा योजनाओं से वंचित रह गए। इनके हित के लिए पहली बार केंद्र सरकार 26 अगस्त को ई-श्रम पोर्टल की शुरुआत की थी। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए, ई-श्रम के मोबाइल एप्लिकेशन या वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं। अगर कोई कर्मचारी ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत है और किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है, तो वह मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर 2.0 लाख और आंशिक विकलांगता पर 1.0 लाख रुपये का पात्र होगा।

स्टार्टअप इंडिया की नई उड़ान: एक तिमाही में पहली बार 10 अरब डॉलर जुटाने के साथ 33 कंपनियां बनीं यूनिकॉर्न

डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया- मेक फॉर द वर्ल्ड, आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल... यह कुछ ऐसे शब्द हैं, जिनके रास्ते बीते 7 सालों में भारत की तरक्की के नए सोपान तय किए हैं। ऐसा ही एक और अभियान है... स्टार्टअप इंडिया। युवा आकांक्षाओं के स्वरोजगार की नई उड़ान देने के लिए जनवरी 2016 में शुरू किया गया स्टार्टअप इंडिया अभियान सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। प्राइस वाटर हाउस कूपर्स इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021 की तीसरी में घरेलू स्टार्टअप कंपनियों ने 347 घरेलू सौदों के जरिए 10.9 अरब डॉलर का रिकॉर्ड कोष जुटाया है। यह किसी भी तिमाही जुटाया गया सबसे बड़ा कोष है। यही नहीं, इस साल अब तक भारत के 33 स्टार्टअप यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो चुके हैं। यूनिकॉर्न क्लब में शामिल स्टार्टअप का वैल्यूएशन एक अरब डॉलर होता है। 10 अरब डॉलर के वैल्यूएशन से अधिक के स्टार्टअप को डेकाकॉर्न कहते हैं। जबकि 100 अरब डॉलर के वैल्यूएशन तक पहुंचने वाले स्टार्टअप को हेक्टोकॉर्न कहा जाता है। आज देश में कुल 66 स्टार्टअप कंपनियां काम कर रही हैं, जिन्हें यूनिकॉर्न का दर्जा मिला है। इनके जरिए करीब 3.3 लाख लोगों को रोजगार मिला है।

साल	यूनिकॉर्न की संख्या
2011-14	1
2015	4
2018	8
2019	9
2020	10
2021	33*

रियल एस्टेट से लेकर अस्पतालों तक जम्मू-कश्मीर में 7 सेक्टरों में निवेश करेगा दुबई

वर्ष 2020-21 में 81 बिलियन डॉलर से ज्यादा के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ भारत ने जहां विदेशी निवेश के मामले में नया रिकॉर्ड बनाया तो अब धरती का स्वर्ग कहे जाने वाला जम्मू और कश्मीर में विदेशी निवेश की नई शुरुआत हुई है। दुबई की सरकार जम्मू कश्मीर में निवेश करने के लिए आगे आई है। रियल एस्टेट, औद्योगिक पार्क, आईटी टावर, निजी अस्पताल जैसी तमाम विकासपरक योजनाओं के लिए दुबई सरकार से समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर सहमति हुई है। इस एमओयू से दुनिया के निवेशक जम्मू कश्मीर में निवेश के लिए प्रोत्साहित होंगे। अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद यह इस क्षेत्र में पहला विदेशी निवेश है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार, "यह समझौता ज्ञापन पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संकेत है कि जिस तरह भारत एक वैश्विक शक्ति में बदल रहा है, उसमें जम्मू-कश्मीर की भी महत्वपूर्ण भूमिका है।"

5000 किमी तक मार करने वाली अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण सफल

बैलेस्टिक रेंज की मिसाइलों के लगातार परीक्षण के बाद 27 अक्टूबर को देश की सबसे ताकतवर मिसाइल कही जाने वाली अग्नि-5 का सफल परीक्षण किया गया। यह मिसाइल पांच हजार किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य भेदने में सक्षम है। मिसाइल के परीक्षण के साथ ही दुनिया के कई देश इसके लक्ष्य की जद में आ गए हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने पहली बार ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से रात में इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अग्नि-5 का यह आठवां सफल परीक्षण है। इसके साथ ही भारत इस तरह की मिसाइल विकसित करने वाला दुनिया का पांचवां देश बन गया है। अभी सिर्फ अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन के पास ही ऐसी मिसाइलें थीं। अग्नि-5 17.5 मीटर लंबी है जिसका व्यास दो मीटर यानी 6.7 फीट है। यह मिसाइल एक सेकेंड में 8.16 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह एक साथ डेढ़ टन तक परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। यह मिसाल महज 20 मिनट में पांच हजार किलोमीटर की दूरी तय करके दुश्मन को तबाह कर सकती है। इसे सड़क के रास्ते कहीं भी पहुंचाया जा सकता है।

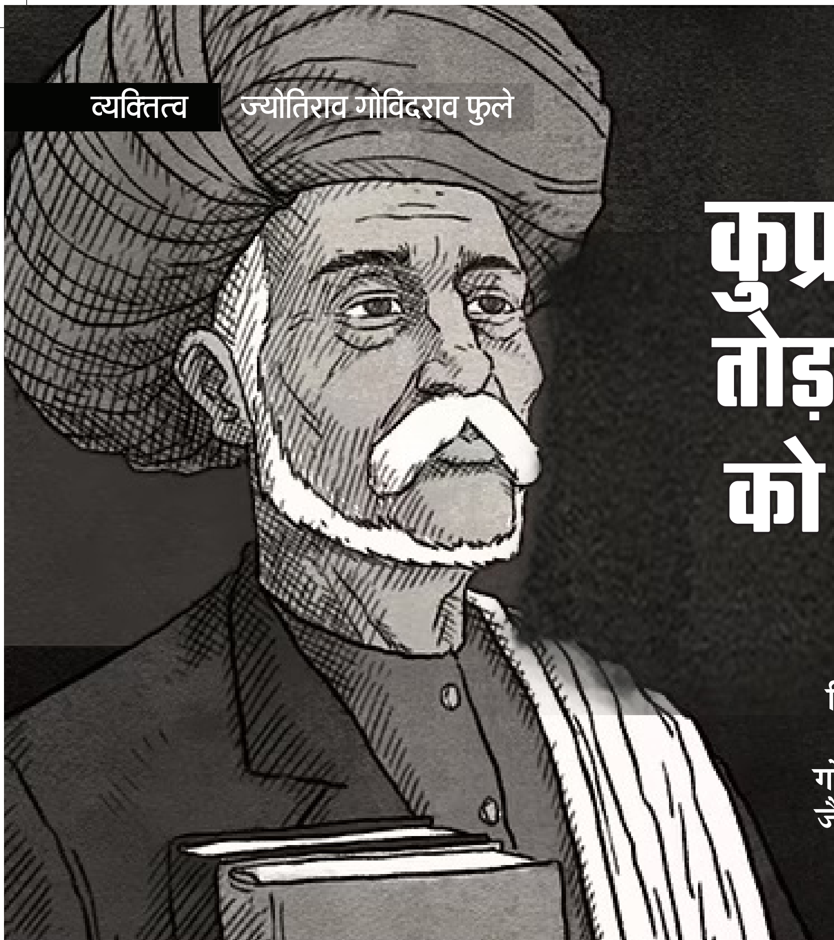

कुप्रथाओं की जंजीर तोड़ महिलाओं-वंचितों को मुख्यधारा में लाए

एक इंसान द्वारा दूसरे इंसान के साथ गुलामों की तरह व्यवहार करना सभ्यता के सबसे शर्मनाक अध्यायों में से एक है तो अफसोस इस बात पर भी होना चाहिए किए यह शर्मनाक अध्याय दुनियाभर की लगभग सभी सभ्यताओं के इतिहास में दर्ज है। लेकिन ज्योतिराव गोविंदराव फुले, जिन्होंने न सिर्फ छुआछूत, बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं के विरोध में आवाज उठाई बल्कि भारत में महिला शिक्षा के जनक के रूप में भी जाने गए...

जन्मः 11 अप्रैल 1827। मृत्युः 28 नवंबर 1890

बात आज से करीब 150 साल पुरानी है। ब्रिटिश राजकुमार और महारानी विक्टोरिया के पौत्र के स्वागत में पुणे में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तमाम बड़े और धनाढ्य लोग, इस कार्यक्रम में पहुंचे। सजधज कर, हीरे-जवाहरातों से लदे लोग वैभव और संपदा के प्रदर्शन में सभी एक-दूसरे को पीछे छोड़ने को जैसे आतुर थे। इसी कार्यक्रम में एक शख्स किसानों की वेशभूषा में पहुंचा। सबके सामने अपने संबोधन में उसने ब्रिटिश राजकुमार से कहा-"धन-धान्य और हीरे-मोती से जड़े हुए कपड़े पहनने वाले लोग हमारे देश का प्रतिनिधित्व नहीं करते क्योंकि उनके जीवन में पैसों का महत्व रोटी से ज्यादा होता है। अगर आप और महारानी वाकई भारतीय प्रजा की स्थिति जानना चाहते हैं तो आसपास के उन गांवों-शहरों का दौरा करिए जहां वे लोग रहते हैं, जिनको अछूत समझा जाता है, जिनके हाथ का पानी पीने, खाना खाने, जिसके साथ खड़े होने पर लोग खुद को अपवित्र मानने लगते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि मेरा यह संदेश आप महारानी विक्टोरिया तक पहुंचा दें और गरीब लोगों को उचित शिक्षा मुहैया कराने का बंदोबस्त करें।"

स्वागत समारोह में मौजूद सभी लोग अवाक रह गए। वैभवभरी उस चकाचौंध के बीच अपने शब्दों से सन्नाटा खींचने वाले उन शख्स का नाम था, ज्योतिराव गोविंद राव फुले। वही ज्योतिबा, जिन्होंने ठाना तो वंचितों और बेटियों के हक के लिए ब्रिटिश शासन

> **महान समाजसेवी, विचारक, दार्शनिक एवं लेखक महात्मा ज्योतिबा फुले को कोटि-कोटि नमन। वे जीवनपर्यंत महिलाओं की शिक्षा और उनके सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध रहे। समाज सुधार के प्रति उनकी निष्ठा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।**
>
> **– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

ही नहीं, उस वक्त के कई मशहूर लोगों से भी भिड़ गए।

पुणे में फूलों से गजरे बनाने वाले परिवार में 11 अप्रैल, 1827 को ज्योतिबा का जन्म हुआ। कहा जाता है कि परिवार लंबे समय से माली का काम करता था। इसलिए लोग उन्हें 'फुले' नाम से जानने लगे। यह वो समय था, जब एक ओर देश अंग्रेजी शासन के खिलाफ खड़ा हो रहा था तो दूसरी ओर देश में जारी छुआछूत, बालविवाह जैसे कुप्रथाओं के खिलाफ भी आवाज उठ रही थी। इसी माहौल के बीच ज्योतिबा ने मराठी में अपनी पढ़ाई की शुरुआत की। लोग पिता से बोले-पढ़ने से तुम्हारा पुत्र किसी काम का नहीं रहेगा। सो पिता ने स्कूल ही छुड़वा दिया। लेकिन पढ़ने की इच्छा दिल में थी सो ज्योतिबा ने 21 वर्ष की उम्र में अंग्रेजी से 7वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी की। 1840 में उनका विवाह सावित्री बाई से हुआ। वही सावित्री, जिनके साथ मिलकर ज्योतिबा ने 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए स्कूल खोला। कहा जाता है कि किसी भारतीय द्वारा खोला जाना वाला यह देश में लड़कियों का पहला स्कूल था। कोई शिक्षक पढ़ाने को राजी नहीं हुआ तो ज्योतिबा ने पहले अपनी पत्नी सावित्री को पढ़ाया और फिर सावित्री ने दूसरी बच्चियों को पढ़ाने की शुरुआत की। इस बात पर हंगामा मच गया कि आखिर कैसे एक नारी शिक्षक बनकर धर्म और समाज से विद्रोह कर सकती है। ज्योतिबा और सावित्री को घर तक छोड़ना पड़ा। लोगों के उलाहनों और आर्थिक तंगी की वजह से स्कूल बंद हो गया। लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। इसके बाद उन्होंने 1849 में जूना गंज पेठ में और फिर 1851 में बुधवार पेठ इलाके में दो और स्कूल खोल डाले। ज्योतिबा और सावित्री बाई ने जो अलख जगाई तो जल्दी ही उनसे प्रेरणा लेकर वंचित समाज की महिलाओं के लिए 18 स्कूल खुल गए। सती प्रथा, बाल विवाह के कट्टर विरोधी ज्योतिबा विधवा विवाह के समर्थक भी थे। पुणे में उन्होंने विधवा आश्रम की शुरुआत की। सावित्री बाई इसकी संयोजक बनीं। बाल विवाह के ज्योतिबा के विरोध को सही मानते हुए अंग्रेजी शासकों ने 1872 में पहली बार भारत में नेटिव मैरिज एक्ट लागू कर 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह को प्रतिबंधित कर दिया। 24 सितंबर 1873 को ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। इस समाज का उद्देश्य महिलाओं, पिछड़ी जाति के लोगों को समाज में न्याय दिलाना था। ज्योतिबा फुले समाज के मुख्य अध्यक्ष थे और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले महिला विभाग की प्रमुख थी। 1876 में वे पूना नगर पालिक के सदस्य बने तो वायसराय लॉर्ड लिटन के स्वागत में होने वाले खर्चे का विरोध करने वाले 36 सदस्यों में वे अकेले थे। उन्होंने बहुत सी किताबें लिखकर जनजागरण का काम किया। 'गुलामगिरी', 'तृतीय रत्न', ' छत्रपति शिवाजी राजे भोसले का पावड़ा', 'किसान का कोड़ा' और 'अछूतों की कैफियत', उनकी श्रेष्ठ कृति हैं। 28 नवंबर 1890 को उनका निधन हो गया। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे नारी सशक्तीकरण के जनआंदोलन की नींव में डेढ़ सौ साल पहले दिए गए ज्योतिबा के वही विचार हैं, जिनमें उन्होंने अशिक्षा को समाज की हर बुराई का जिम्मेदार ठहराया था। वो एक महान विचारक, निस्वार्थ समाजसेवी तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। उन्होंने भारतीय सामाजिक संरचना की जड़ता को ध्वस्त करने का काम किया। महिलाओं और वंचितों की अपमानभरी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए वे उस दौर में हमेशा लड़ते रहे, जब यह सबसे कठिन काम था।●

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे नारी सशक्तीकरण के जनआंदोलन की नींव में डेढ़ सौ साल पहले दिए गए ज्योतिबा के वही विचार हैं, जिनमें उन्होंने अशिक्षा को समाज की हर बुराई का जिम्मेदार ठहराया था।

सात आयुध फैक्ट्रियां से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की नई उड़ान

आजादी के बाद अनदेखी की शिकार आयुध फैक्ट्रियों को अमृत महोत्सव वर्ष में मिली नई आजादी देश के गौरवशाली आयुध कारखानों की पहचान वापस दिलाएगी और रक्षा क्षेत्र में राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाते हुए पूरा करेगी सेना की हर अस्त्र-शस्त्र की जरूरत, साथ ही रक्षा सामग्री के निर्यात में अग्रणी बनेगा भारत

अतीत में भारत की आयुध फैक्ट्रियों का दो शताब्दियों से भी अधिक लंबा इतिहास रहा है जो कभी दुनिया की शक्तिशाली संस्थाओं में गिनी जाती थीं। इन फैक्टरियों के पास सौ-डेढ़ सौ साल से भी ज्यादा का अनुभव है। विश्व युद्ध के समय भारत की ऑर्डिनेन्स फैक्ट्रियों का दम-खम दुनिया ने देखा है। तब बेहतर संसाधन होते थे, विश्व स्तरीय कौशल होता था। लेकिन आजादी के बाद लंबे समय तक इन फैक्ट्रियों को आधुनिक बनाने की दिशा में जो काम होना चाहिए था, वह नहीं हुआ। परिणाम हुआ कि भारत लंबे समय तक अपनी सामरिक जरूरतों के लिए विदेशों पर निर्भर होता चला गया। लेकिन सैन्य शक्ति को प्राथमिकता दे रही केंद्र सरकार ने देश के जांबाज जवानों के शौर्य और पराक्रम को आयुध फैक्ट्रियों के जरिए आवश्यक अस्त्र-शस्त्र, गोला-बारूद आदि की आपूर्ति करने की दिशा में एक और कदम उठाया है। दशहरा उत्सव के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 नई रक्षा कंपनियों को राष्ट्र को

> **भारत नए भविष्य के निर्माण के लिए नए संकल्प ले रहा है। हमारा मेक इन इंडिया मंत्र एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के हमारे संकल्प को मजबूत कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश का लक्ष्य भारत को अपने दम पर दुनिया की बड़ी सैन्य शक्ति बनाने का है। ये 7 नई रक्षा कंपनियां भारत की सैन्य शक्ति का बड़ा आधार बनेंगी।**
>
> **– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने के लिए QR कोड स्कैन करें।

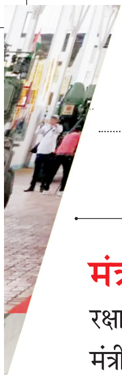

ऐसे बदल रही तस्वीर

मंत्री समूह रखेगा निगाह

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाला एक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह इस कार्य की पूरी प्रक्रिया पर निगाह रखेगा। ●अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री ● निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त मंत्री ● किरेन रिजीजू, केंद्रीय विधि व न्याय मंत्री ● भूपेंद्र यादव, केंद्रीय पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन व श्रम रोजगार मंत्री ● जितेन्द्र सिंह, राज्यमंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश का लक्ष्य भारत को अपने दम पर दुनिया की बड़ी सैन्य ताकत बनाना और आधुनिक सैन्य इंडस्ट्री का विकास करना है। पिछले सात वर्षों में देश ने 'मेक इन इंडिया' मंत्र के साथ अपने इस संकल्प को आगे बढ़ाते हुए पारदर्शिता के साथ रक्षा क्षेत्र में बड़े सुधार किए हैं और सिंगल विंडो सिस्टम को तरजीह दी है। नीतिगत बदलावों का ही परिणाम है कि बीते पांच वर्षों में भारत का रक्षा निर्यात 325 फीसदी से भी ज्यादा बढ़ा है। ऐसे में बदलते वक्त के अनुरूप इन आयुध फैक्ट्रियों को ढालकर आगे बढ़ाने की पहल 16 जून 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक ऐतिहासिक फैसले से की थी, जिसके तहत आयुध फैक्ट्री बोर्ड को समाप्त करके 7 नए रक्षा उपक्रम बनाने को मंजूरी दी। यह सुनिश्चित किया गया है कि आयुध फैक्ट्रियों को कॉरपोरेट में बदलने की प्रक्रिया में इससे जुड़े हितधारकों और कर्मचारियों के हित पूरी तरह सुरक्षित रहें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाला एक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह इस कार्य की पूरी प्रक्रिया पर पूरी पैनी निगाह रखेगा। दूरदर्शी निर्णय हमेशा इतिहास बदलने वाला होता है और बेहतर भविष्य का निर्माण करता है। ऐसे में ये सात कंपनियां अब नए भारत की नई राह पर चलकर रक्षा उत्पादों के आयात का विकल्प, विविध रक्षा सामग्री के निर्माण के साथ-साथ नए अवसरों की तलाश कर निर्यात को बढ़ाने में भी योगदान देंगी। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार ने आयुध फैक्ट्री बोर्ड के 65 हजार करोड़ रुपये के कांट्रैक्ट इन कंपनियों को हस्तांतरित किए हैं। इससे पहले रक्षा मंत्रालय ने ऐसे 100 से ज्यादा सामरिक उपकरणों की लिस्ट जारी की थी जिन्हें अब बाहर से आयात नहीं किया जाएगा। निश्चित तौर से यह नई पहल एक सुनहरे युग की शुरुआत करेगा और आयुध निर्माण में पूरे विश्व में भारत का परचम लहराएगा।

स्वायत्तता के साथ दक्षता को तरजीह

सरकार ने देश की रक्षा तैयारियों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए एक उपाय के तौर पर आयुध निर्माण बोर्ड को सरकारी विभाग से सात कंपनियों को शत-प्रतिशत सरकारी स्वामित्व वाली कॉरपोरेट कंपनियों में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। यह कदम बेहतर कार्यात्मक स्वायत्तता एवं दक्षता सुनिश्चित करेगा और विकास की नई संभावनाओं एवं इनोवेशन का मार्ग प्रशस्त करेगा।

जिन सात नई रक्षा कंपनियों को सूचीबद्ध किया गया है, उनमें शामिल हैं: म्यूनिशन्स इंडिया लिमिटेड (एमआईएल); आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड (अवनी); एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड (एडब्ल्यूई इंडिया); ट्रूप कम्फर्ट्स लिमिटेड (टीसीएल); यंत्र इंडिया लिमिटेड (वाईआईएल); इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (आईओएल) और ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड (जीआईएल)।

रक्षा उत्पादन के निर्यात से राजस्व का लक्ष्य

11000 करोड़ रु. राजस्व 2020-21

28000 करोड़ रु. अनुमानित 2024-25 तक

समर्पित कर शक्तिशाली भारत के अपने संकल्प को दोहराया है। देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित इन 7 रक्षा उपक्रमों के अंतर्गत आने वाली 41 फैक्ट्रियों में व्यापक सुधार कर इन्हें अधिक उत्पादक और प्रतियोगी बनाकर नई चुनौतियों के लिए तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।●

सुरक्षित महिला
समृद्ध राष्ट्र
की शक्ति

पुरुषों के समान कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी हो तो भारत की जीडीपी को 27 फीसदी और विकास दर को डेढ़ फीसदी तक बढ़ाया जा सकता है। इसी सोच के साथ केंद्र सरकार ने बीते कुछ वर्षों में महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है तो एक साथ तीन तलाक, महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा और अपराधों के खिलाफ सख्त कानून बनाए हैं, ताकि नारी शक्ति को सुरक्षा भाव के साथ मिले लैंगिक न्याय व समानता के अवसर और बने राष्ट्र की समृद्धि की पहचान। महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए जागरूक करने के लिए संयुक्त राष्ट्र हर साल 25 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस के रूप में मनाता है, ऐसे में यह जानते हैं कि किन प्रयासों से कितना सुरक्षित हो रहा है नारी शक्ति के लिए नया भारत

घटना देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की है। 30 नवंबर 2019 का दिन था। 31 वर्षीय जन्नत बेगम पटेल के वॉट्सएप पर उनके पति का एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है- तलाक,तलाक, तलाक। जन्नत उस समय 7 माह की गर्भवती थीं। ससुराल वाले उन्हें दहेज के लिए काफी अरसे से परेशान कर रहे थे।

ऐसी ही एक घटना उत्तराखंड के जसपुर इलाके में दिसंबर 2020 में हुई है। दहेज की मांग पूरी न होने पर मुमताज को उसके पति ने एक साथ तीन तलाक कहकर घर से निकाल दिया गया।

एक साथ तीन तलाक देने के ऐसे कई मामले आपने 2019 के पहले भी सुने होंगे। जैसे इंदौर का मशहूर शाहबानो का मामला। लेकिन उनमें और इन किस्सों में एक फर्क है। जन्नत और मुमताज, दोनों ने ही अपने पति और ससुराल वाले के खिलाफ नए तीन तलाक कानून के तहत मामला दर्ज कराया। 1 अगस्त 2019 को इस कानून के लागू होने के तत्काल बाद 2 अगस्त को पति के खिलाफ एफआईआर कराने वाली जन्नत देश की पहली महिला हैं। दोनों ही मामलों में पति की गिरफ्तारी हुई है। जो न्याय शाहबानो को नहीं मिला, अब देश की हर मुस्लिम महिला को मिला है। इस कानून की महत्ता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इस कानून के लागू होने के बाद सिर्फ दो साल में ही तीन तलाक के मामले में 80 से 82 फीसदी की कमी आई है, जो मुस्लिम महिलाओं को आत्मसम्मान और सुरक्षा का भाव प्रदान करने वाली है।

लड़कियां हों या युवतियां, महिलाएं हों या बुजुर्ग माताएं, अगर आज लड़ने का साहसिक कदम उठा पा रही हैं तो उसकी वजह है- बीते कुछ वर्षों में सामाजिक वर्जनाओं को तोड़कर की गई कानूनी पहल, ताकि हर नारी अपने अधिकारों के प्रति सजग होकर मुकाबला कर सके। महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा के मामले में कानूनी प्रावधानों को इतना सख्त और तीव्र बनाया गया है कि बलात्कार जैसे मामलों में वर्षों की बजाए चंद दिनों में न्याय मिलने लगा है।

2014 में जहां महिला पुलिस कर्मियों की संख्या 1 लाख 5 हजार के करीब थी, वहीं 2020 तक ये संख्या 2 लाख 15 हजार तक पहुंच गई है।

कुछ मामलों में तो 24 घंटे में भी फैसला आने लगा है। जयपुर की पॉक्सो कोर्ट ने हाल में ही 10 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म के मामले में सिर्फ 9 दिनों में फैसला सुनाया है। कुरीतियों पर कुठाराघात ही नहीं, महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के खिलाफ केंद्र सरकार के सख्त कदमों ने भी नारी शक्ति को सुरक्षित माहौल दिया है जो राष्ट्र की प्रगति का आधार बन रही हैं। महिलाओं के नेतृत्व में विकास के विजन के साथ सरकार महिला सशक्तीकरण के लिए सतत प्रयासरत है। चाहे शिक्षा हो या खेल, रक्षा हो या उद्यमिता, देश की बेटियां आज सभी बाधाओं को तोड़ अपना प्रभाव स्थापित कर रही हैं तो इसकी वजह है- महिला सुरक्षा और सुविधाओं को मिली सर्वोच्च प्राथमिकता। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट बताती है कि पुरुषों के समान महिलाओं की कार्यबल में हिस्सेदारी से भारत की जीडीपी में 27 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर 50 प्रतिशत कुशल महिलाएं कार्यबल में शामिल होती हैं, तो विकास दर 1.5 प्रतिशत बढ़कर 9 प्रतिशत प्रति वर्ष हो सकता है।

केंद्र सरकार निरंतर महिलाओं को समानता के अवसर और सुरक्षित वातावरण देने के लिए नई-नई पहल कर रही है। इन्हीं अथक प्रयासों का नतीजा है कि आज न्याय की आस में न्यायालय का दरवाजा खटखटाना हो या अपने खिलाफ होने वाली हिंसा का पुरजोर विरोध कर अपराधियों के हौसले पस्त करना। राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व हो या सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान राफेल उड़ाना या मोर्चे पर दुश्मनों से मुकाबला करना या खेल जगत में देश का नाम रोशन करना या फिर स्वरोजगार के अवसरों का लाभ उठाकर बराबरी के साथ देश को आर्थिक मजबूती देना, महिला शक्ति सिर्फ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल रहीं बल्कि कहीं आगे निकल राष्ट्र का अभिमान बन रही हैं।

सशक्त भारत के लिए नारी शक्ति की सुरक्षा

एक राष्ट्र, एक आपातकालीन नंबर 112 लांच। 35 राज्यों-केंद्रशासित प्रदेशों में चालू किया गया।

समाधान

फरवरी 2021 तक 11 करोड़ से अधिक कॉल्स का निपटारा, लगभग 1 मिलियन एप यूजर्स में 47% महिलाएं हैं।

डीएनए विश्लेषण इकाइयां

कुल 190 करोड़ रुपये की लागत से 20 राज्यों-केंद्रशासित प्रदेशों में डीएनए विश्लेषण इकाइयों की स्थापना और अपग्रेडिंग को स्वीकृति।

वन स्टॉप सेंटर

निजी, सार्वजनिक, परिवार, समुदाय या कार्यस्थल पर हिंसा से पीड़ित महिलाओं के सहायता के लिए देश भर में 701 वन स्टॉप सेंटर संचालित, जिसमें 3 लाख से अधिक महिलाओं को मिली सहायता।

तीन तलाक खत्म

19 सितंबर 2018 से लागू मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 लागू हुआ। मुस्लिम महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा हुई सुनिश्चित।

सख्त कानूनी प्रावधान

महिलाओं के खिलाफ अपराध कम करने की दिशा में पहल। आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 को पारित कर बलात्कार के दोषियों के लिए फांसी सहित कड़ी सजा का प्रावधान।

फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट

यौन अपराधों से संबंधित मुकदमों की त्वरित सुनवाई के लिए 1023 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायलयों की स्थापना। कोविड महामारी के दौरान भी बलात्कार और पॉक्सो से संबंधित 49 हजार से अधिक लंबित मामलों का निपटारा किया गया।

शी (She)

यौन उत्पीड़न के मामले में शिकायत करने और उसकी निगरानी के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की शुरुआत 2017 में की गई।

आत्मरक्षा की पहल

समग्र शिक्षा अभियान के तहत सरकारी स्कूलों में कक्षा 6-12 तक की लड़कियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाने की शुरुआत।

ओलंपिक में महिला एथलीटों का प्रदर्शन

प्रतिभागियों की संख्या 2008 में 25 थी, जो 2012 में 23 रह गई। जबकि प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में 2016 में 54 थी जो 2020 में बढ़कर 57 हो गई।

> एक पुरातन और मध्यकालीन परंपरा इतिहास में दफन हो गई। संसद ने तीन तलाक को खत्म कर दिया और मुस्लिम महिलाओं के प्रति हुई ऐतिहासिक गलती को सुधार दिया गया। यह लैंगिक न्याय की जीत है और इससे समाज में समानता को बढ़ावा मिलेगा। भारत आज प्रफुल्लित है। यह मुस्लिम महिलाओं के असाधारण साहस को सलाम करने का अवसर है, जिन्हें तीन तलाक की प्रथा के कारण भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तीन तलाक की प्रथा खत्म होने से महिलाओं के सशक्तिकरण में इजाफा होगा और महिलाओं को समाज में वह गरिमा प्राप्त होगी, जिसकी वे हकदार हैं।
>
> – नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री (तीन तलाक पर लोकसभा से कानून पारित होने पर)

महिलाओं ने अपनी अद्भुत क्षमता से यह साबित कर दिखाया है कि अगर उन्हें समान अवसर मिले तो सिर्फ घर ही नहीं, एक समृद्ध, गौरवशाली राष्ट्र का भी निर्माण कर सकती हैं।

आधी आबादी के सपनों को मिल रही सुरक्षा

भारत की नारीशक्ति के सामने आजादी के इतने दशकों बाद भी अनेक रुकावटें बनी हुई थीं। बहुत से क्षेत्रों में तो उनके प्रवेश पर भी पाबंदी थी और महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा था। लेकिन आज महिलाओं के लिए काम के अनेक क्षेत्रों को न सिर्फ खोल दिया गया है, बल्कि वो 24 घंटे सुरक्षा के साथ काम कर सकें, इसे भी सुनिश्चित किया जा रहा है। दुनिया के चुनिंदा देशों में भारत भी शामिल है जिसने नौकरी

कई बेटियां सबसे कठिन ट्रेनिंग के बाद कोबरा बटालियन का हिस्सा बनने जा रही हैं।

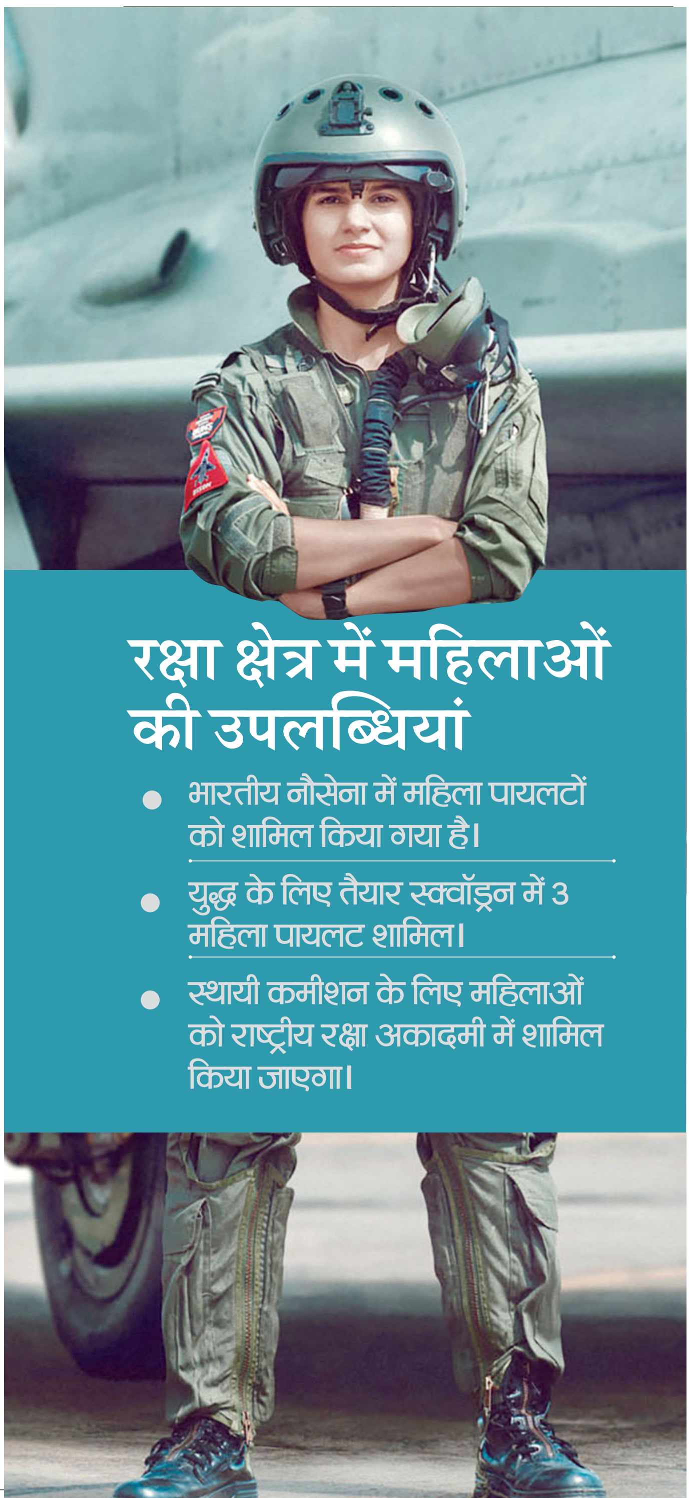

रक्षा क्षेत्र में महिलाओं की उपलब्धियां

- भारतीय नौसेना में महिला पायलटों को शामिल किया गया है।
- युद्ध के लिए तैयार स्क्वॉड्रन में 3 महिला पायलट शामिल।
- स्थायी कमीशन के लिए महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में शामिल किया जाएगा।

करने वाली आत्मनिर्भर महिलाओं को वेतन के साथ 26 हफ्ते की छुट्टी का कानूनी अधिकार दिया है क्योंकि जब महिला को 26 सप्ताह की छुट्टी मिलती है तो वो एक प्रकार से अपने नवजात बच्चे के अधिकार की रक्षा करती है। उस नवजात का अधिकार है उसकी मां के साथ जिंदगी बिताने का। इतना ही नहीं, बेटियों की सुरक्षा से जुड़े भी अनेक कानूनी कदम बीते सालों में उठाए गए हैं। देश के 700 से अधिक जिलों में वन स्टॉप सेंटर्स चल रहे हैं, जहां एक ही जगह पर महिलाओं को मेडिकल सहायता, पुलिस सुरक्षा, साइको सोशल काउंसलिंग, कानूनी मदद और अस्थायी आश्रय दिया जाता है। महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों की जल्द से जल्द सुनवाई हो, इसके लिए देशभर में साढ़े छह सौ से ज्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई हैं। बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के लिए मौत की सजा का प्रावधान भी किया गया है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में संशोधन करके महिलाओं को गर्भपात से जुड़ी स्वतंत्रता दी गई है। सुरक्षित और कानूनी गर्भपात का रास्ता मिलने से महिलाओं के जीवन पर संकट भी कम हुआ है और प्रताड़ना से भी मुक्ति मिली है। बच्चों से जुड़े अपराधों पर लगाम लगाने के लिए भी कानूनों को कड़ा किया गया है।

बीते वर्षों में देश ने अलग-अलग वर्गों में, अलग-अलग स्तर पर हो रहे अन्याय को भी दूर करने का प्रयास किया है। दशकों से मुस्लिम महिलाएं तीन तलाक के खिलाफ कानून की मांग कर रही थीं। ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाकर, मुस्लिम महिलाओं को नया अधिकार दिया गया है। मुस्लिम महिलाओं को हज के दौरान महरम की बाध्यता से मुक्त करने का काम भी केंद्र सरकार की प्रगतिशील सोच का उदाहरण है।

लैंगिक समानता की नजीर ट्रिपल तलाक कानून

सरकार सिर्फ शासन करने के लिए नहीं होती, बल्कि वह उन लाखों करोड़ों लोगों की उम्मीदों का भी प्रतिनिधित्व करती है, जो अपनी आंखों में बेहतर भविष्य के सपने लिए उससे अपेक्षा रखते हैं। ऐसे में जरूरत होती है कड़े फैसले करने की, जो देश के साथ आम जन के बेहतर भविष्य की बुनियाद बनते हैं। 30 जुलाई 2019 को भी एक ऐसे ही फैसले की घड़ी थी, जब तलाक-ए-बिद्दत को प्रतिबंधित करने वाले कानून को संसद से पारित कराया गया। उन करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को उनका हक मिला जिसकी आस पहली बार 1985 में जगी थी, और 1986 में उसने दम भी तोड़ दिया क्योंकि अंतिम फैसले की घड़ी के वक्त प्रतिबद्धता में कहीं कमी रह गई। लेकिन इसके 33 साल बाद मिले नए कानून के साथ उन्हें पहली बार सम्मान के साथ जीने का हक मिला है।

कहीं न कहीं यह सवाल खड़े करता है कि आखिर महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए कानूनी प्रावधान पहले क्यों नहीं किए गए? आखिर ऐसी क्या वजह थी कि 1986 में जब सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो मामले

स्वस्थ महिला सुरक्षा का आधार

कुपोषण के खिलाफ राष्ट्रव्यापी पोषण अभियान चलाया जा रहा है। पिछले 4 वर्षों में 11 हजार करोड़ रुपये अधिक का आवंटन हुआ तो मिशन इंद्रधनुष और मातृत्व वंदना जैसी योजनाओं के जरिए महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र पर खास ध्यान दिया गया है।

₹11000 करोड़ से अधिक का आवंटन हुआ। कुपोषण के खिलाफ राष्ट्रव्यापी पोषण अभियान में पिछले 4 वर्षों में।

बेहतर पोषण परिणामों के लिए अब पोषण 2.0 शुरू किया गया।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से स्वस्थ मातृत्व सुनिश्चित हो रहा।

गर्भवती महिलाओं को सहारा

गर्भवती और दुग्धपान कराने वाली माताओं के बैंक खाते में सीधे 5 हजार रुपये की राशि (तीन किस्तों में) प्रोत्साहन के रूप में।

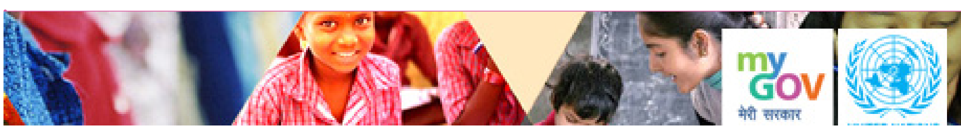

जनवरी 2021 तक में 1.83 करोड़ गर्भवती महिलाओं ने इस योजना का लाभ उठाया।

आत्मनिर्भर महिला शक्ति

- स्टार्ट अप इंडिया के तहत नारी शक्ति मिसाल कायम कर रही हैं।
- लगभग आधे स्टार्टअप में महिला उद्यमी हैं, जिनमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कम से कम 1 महिला निदेशक हैं।
- स्टैंड अप इंडिया योजना से महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिल रहा है।
- इसमें 90 हजार से अधिक महिलाओं के लिए 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक के ऋण की मंजूरी।
- इस योजना के तहत 83 % ऋण महिला उद्यमी को दिया गया है।
- मार्जिन मनी को 25% से घटाकर 15% कर ऋण को सुलभ किया गया।

में फैसला दिया तो उसे मानने की बजाए संसद के रास्ते कोर्ट के फैसले को ही निष्प्रभावी कर दिया गया? अगर इस देश में सती प्रथा को खत्म कर सकते हैं, भ्रूण हत्या को खत्म करने के कानून बना सकते हैं, अगर बाल-विवाह के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, दहेज में लेन-देन की प्रथा के खिलाफ कठोर कदम उठा सकते हैं, तो क्यों न तीन तलाक के खिलाफ भी आवाज उठाया गया? इसके लिए सरकार में बैठे लोगों के दृष्टिकोण को समझना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब भी ट्रिपल तलाक कानून को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने दो-टूक कहा, "यह काम हमने वोट के लिए नहीं किया। मैं सरकार दल के लिए नहीं चला रहा हूं, बल्कि देश के भविष्य के लिए चला रहा हूं। ट्रिपल तलाक कानून मेरे लिए हिंदू-मुस्लिम का नहीं, नारी सम्मान का विषय है। मुस्लिम देशों में भी ट्रिपल तलाक को मान्यता नहीं है। पाकिस्तान में भी कानूनी रोक है। बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा, दहेज प्रथा जैसे विषयों पर कदम उठाए गए तो क्या यह हिंदुओं के खिलाफ था। इसलिए ट्रिपल तलाक भी लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय का मामला है। भारत इस मत का है कि सभी को समानता मिलनी चाहिए।"

दरअसल 'तीन तलाक' या 'तलाक-ए-बिद्दत' जो ना संवैधानिक तौर से ठीक था, ना इस्लाम के नुक्तेनजर से जायज था। फिर

पाकिस्तान, मिस्त्र, सीरिया, ईराक, मलेशिया जैसे कई इस्लामिक देश तीन तलाक की प्रथा पर वर्षों पहले रोक लगा चुके हैं।

भी देश में मुस्लिम महिलाओं के उत्पीड़न से भरपूर गैर-कानूनी, असंवैधानिक, गैर-इस्लामी कुप्रथा 'सियासी संरक्षण' में फलता-फूलता रहा। 'तीन तलाक' कुप्रथा के खिलाफ कानून तो 1986 में भी बन सकता था जब शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया था। जबकि भारत संविधान से चलता है, किसी शरीयत या धार्मिक कानून या व्यवस्था से नहीं। इससे पहले भी देश में सती प्रथा, बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने के लिए भी कानून बनाये गए। तीन तलाक कानून का किसी मजहब, किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं था, शुद्ध रूप से यह कानून एक कुप्रथा, क्रूरता, सामाजिक बुराई और लैंगिक असमानता को खत्म करने के लिए पारित किया गया। यह मुस्लिम महिलाओं के समानता के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा से जुड़ा विषय था। मौखिक रुप से तीन बार तलाक कह कर तलाक देना, पत्र, फोन, यहां तक की मैसेज, व्हाट्सएप के जरिये तलाक दिए जाने के मामले सामने आने लगे थे, जो कि किसी भी संवेदनशील देश-समावेशी सरकार के लिए अस्वीकार्य था। दुनिया के कई प्रमुख इस्लामी देशों ने बहुत पहले ही 'तीन तलाक' को गैर-कानूनी और गैर-इस्लामी घोषित कर खत्म कर दिया था। मिस्त्र दुनिया का पहला इस्लामी देश है जिसने 1929 में "तीन तलाक" को खत्म किया, गैर कानूनी एवं दंडनीय अपराध बनाया। 1929 में सूडान ने तीन तलाक पर प्रतिबन्ध लगाया। 1956 में पाकिस्तान ने, 1972 में बांग्लादेश, 1959 में इराक, सीरिया ने 1953 में, मलेशिया ने 1969 में इस पर रोक लगाई। इसके अलावा साइप्रस, जॉर्डन, अल्जीरिया, ईरान, ब्रूनेई, मोरक्को, कतर, यूएई जैसे इस्लामी देशों ने तीन तलाक खत्म किया और कड़े कानूनी प्रावधान बनाये। लेकिन भारत को मुस्लिम महिलाओं को इस कुप्रथा के अमानवीय जुल्म से आजादी दिलाने में लगभग 70 साल लग गए।

भारत के संसदीय इतिहास में 1 अगस्त की तारीख अब 'मुस्लिम महिला अधिकार दिवस' के रूप में दर्ज हो चुकी है। 1 अगस्त 2019

ट्रिपल तलाक: मामलों में आ रही गिरावट

आंकड़े: 1985-2019 | 2019-20

राज्य	1985-2019	2019-20
उत्तर प्रदेश	63,400	281
तेलंगाना-आंध्र	41,382	203
हरियाणा	29,201	26
केरल	23,233	19
राजस्थान	33,112	83
असम	19,008	17
मध्य प्रदेश	22,801	32
प. बंगाल	51,800	201
महाराष्ट्र	39,200	102
बिहार	21,200	26

> परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण इन तीन चीजों ने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया किंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून के बनने के बाद लोगों को इस बात की खुशी है कि भारत का लोकतंत्र धीरे-धीरे पटरी पर आ रहा है। इस समाज को आगे बढ़ाने में राजा राम मोहन राय, वीर सावरकर, महात्मा गांधी, डॉ. भीम राव अंबेडकर समेत तमाम समाज सुधारकों का हाथ है और उन लोगों ने देश की कुप्रथाओं को समाप्त करने में अपना योगदान दिया, समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है। जब भी देश के समाज सुधारकों का नाम लिया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम भी समाज सुधारकों की श्रेणी में शामिल होगा।
> – अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री

ट्रिपल तलाक के अभिशाप से मुक्त महिलाएं

समस्याओं का जब समाधान होता है, तो स्वावलंबन का भाव पैदा होता है। समाधान से स्वावलंबन की ओर गति बढ़ती है और जब समाधान हो, संकल्प हो, सामर्थ्य हो, तब सफलता के आड़े कुछ नहीं आ सकता है। प्रधानमंत्री मोदी की यही सोच उनके दृढ़ फैसलों का आधार है। वे कहते हैं, "हम समस्याओं का समाधान देखते हैं, तो टुकड़ों में नहीं सोचना चाहिए। तकलीफें आयेंगी, एक साथ वाहवाही के लिये हाथ लगाकर छोड़ देना, यह तरीका देश के सपनों को साकार करने के काम नहीं आयेगा। हमें समस्याओं को जड़ों से मिटाने की कोशिश करनी होगी।" समग्र दृष्टिकोण से उठाए गए कदमों का ही परिणाम है कि आज मुस्लिम महिलाएं ट्रिपल तलाक के अभिशाप से मुक्त हैं। जबकि मुस्लिम महिलाओं के सिर पर तीन तलाक की तलवार लटकती थी और वे डरी हुई जिंदगी जीने को मजबूर थीं। हमेशा यह डर सताता था कि वे कभी भी तीन तलाक की शिकार हो सकती हैं। असुरक्षा का भाव उनके जीवन को कठिन बनाता था। ट्रिपल तलाक को समाप्त करने का रास्ता आसान नहीं था, लेकिन मोदी सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण सफलता प्राप्त हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं, "यदि समय के साथ समाज नहीं बदलता है तो गंदे तालाब जैसा बन जाता है और समय के साथ बदलने वाला समाज निर्मल गंगा की तरह पवित्र हो जाता है।"

शाहबानो केस से शायरा बानो केस तक क्या फर्क है ?

	शाहबानो केस	शायरा बानो केस
किसे चुनौती	तीन तलाक के बाद कम गुजारा भत्ता	तलाक-ए-बिद्दत
सुप्रीम कोर्ट में कब पहुंचा केस	1981	2016
कब फैसला आया	1985	2017
क्या फैसला आया	तीन तलाक में भी महिला गुजारे भत्ते की हकदार	तीन तलाक असंवैधानिक
शीर्ष स्तर पर भूमिका	कानून बनाकर फैसला पलटा	नया कानून बना हक दिया

भारतीय संसद के इतिहास का वह दिन है जिस दिन 'तीन तलाक' कुप्रथा को खत्म करने के विधेयक को कानून बनाया गया। देश की आधी आबादी और मुस्लिम महिलाओं के लिए यह दिन संवैधानिक-मौलिक-लोकतांत्रिक एवं समानता के अधिकारों का दिन बन गया। यह दिन भारतीय लोकतंत्र और संसदीय इतिहास के स्वर्णिम पन्नों का हिस्सा रहेगा। एक वक्त था जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी बनाते हुए मुस्लिम महिलाओं को अधिकारों से वंचित कर दिया गया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 'तीन तलाक' पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने का साहसिक कदम उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई 2017 को तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिया था। इसके बाद केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई और बाद में तमाम विरोधों के बावजूद जुलाई-अगस्त 2019 में संसद से इस कानून को पारित कराया गया और राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही यह सितंबर 2018 से प्रभावी माना गया।

महिला सुरक्षा की नई राह

वही समाज प्रगति कर सकता है जो महिलाओं का सम्मान करता हो। महिलाएं अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल कर सके, इसके लिए उसका शिक्षित होना जरूरी है ताकि वे अपना भविष्य खुद तय कर सके। शिक्षा अपने साथ रोजगार और उद्यमशीलता लेकर आती है तो रोजगार और उद्यमशीलता अपने साथ लाती हैं- आर्थिक स्वतंत्रता। ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा से लेकर स्वावलंबन बनाने की दिशा में बीते कुछ वर्षों में केंद्र सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं जिससे आधी आबादी को अपनी हुनर दिखाने का सुरक्षित माहौल मिल रहा है। लंबे समय से मांग थी कि महिलाओं के खिलाफ अपराध को संगीन मानते हुए कठोर सजा का प्रावधान किया जाए। इसके लिए केंद्र सरकार ने भारतीय दंड संहिता में बदलाव करते हुए 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से बलात्कार पर कानून को सख्त

टैक्सियों में जीपीएस और पैनिक बटन जैसी व्यवस्था पहली बार महिला सुरक्षा को ध्यान में रखकर की गई है।

बनाते हुए फांसी की सजा का प्रावधान किया तो 16 साल से कम उम्र की लड़कियों से बलात्कार के मामले में सजा को 10 साल से बढ़ाकर 20 साल कर दिया गया। महिलाओं को त्वरित न्याय मिले, इसके लिए भी जांच और ट्रायल को 2 महीने में पूरा करने का प्रावधान किया गया ताकि पीड़ित परिवारों और गवाहों को प्रभावित कर धमकाया न जा सके।

हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए यूनीवर्सल हेल्पलाइन (181) शुरू की गई तो सरकारी और निजी कार्यस्थलों, मेट्रो और अन्य शहरों में भी महिला सुरक्षा के लिए 'शी-बॉक्स' बनाया गया। घरेलू हिंसा जैसे मामलों से निपटने के लिए वन स्टॉप सेंटर बनाए गए हैं। निर्भया फंड से देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट, महिला हेल्प डेस्क और हिम्मत एप शुरू किया गया जो पुलिस और महिला के बीच एक सेतु का काम करता है। बालिकाओं और महिलाओं की तस्करी पर रोक लगाने के लिए संसद में बिल लाया गया जो यह सुनिश्चित करता है कि ऐसे मामलों को तत्काल ट्रैक किया जा सके और न्याय मिले। इसके तहत जबरन मजदूरी, वेश्यावृत्ति, यौन शोषण, जबरन विवाह आदि के लिए सजा का प्रावधान है।

सिर्फ कानूनी संरक्षण ही नहीं, महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए केंद्र सरकार ने तो मानो अभियान ही चला रखा है। घर-घर शौचालय का निर्माण हो या फिर पीएम आवास योजना के तहत संपत्ति में मालिकाना हक महिलाओं को सौंपना, मुद्रा लोन लाभार्थी में 70 फीसदी महिलाएं, उज्ज्वला के तहत मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन आदि पहल महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित कर रहा है। जम्मू-कश्मीर में गैर कश्मीरी से विवाह करने पर महिलाओं और उसके बच्चों को पैतृक संपत्ति के हक से वंचित कर दिया जाता था। लेकिन अनुच्छेद 370 और 35 ए को निरस्त किए जाने के बाद इस क्षेत्र की महिलाओं को उसका हक मिला है। प्रवासी भारतीयों द्वारा शादी करने और फिर छोड़ देने जैसे मामलों में भी कानून को सख्त बनाया गया है।

सामाजिक धारणाओं की नई परिभाषा अब केंद्र सरकार की महिला केंद्रित पहल से मिलती है। महिलाओं को समान अवसर और समय

ताकि सक्षम रहें महिला शक्ति

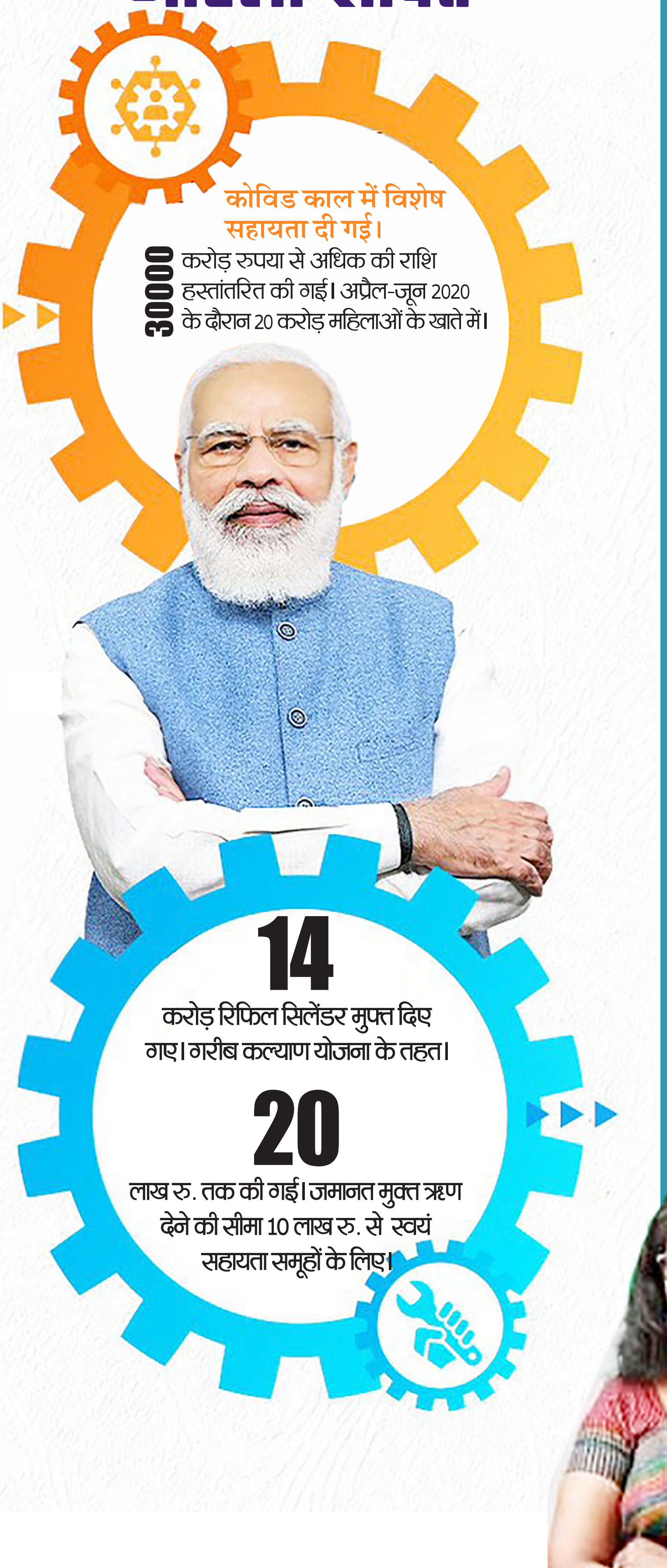

नारी तू नारायणी

तुमसे ही सामर्थ्य है, तुम्ही हो राष्ट्रशक्ति।
बिना तुम्हारे हर बात अधूरी लगती।
घर, बिजली, शौचालय, पानी, एलपीजी ने
सशक्त बनाया है।
शिक्षा, स्वास्थ्य है, पोषण-कौशल और हिम्मत ने
तुझे आगे बढ़ाया है।
खेल हो या युद्ध का मैदान या फिर बात विज्ञान-
तकनीक की।
हर मैदान की है चैंपियन, मौका मिलते ही ये बात है
तुमने साबित कर दी।
नहीं किसी से कम तू, हमेशा अग्रणी,
अभिमानी, नारी तू नारायणी।
स्वतंत्रता, सुविधा, सशक्तीकरण से अब मिल रही
तुम्हें आर्थिक आजादी।
देश बनेगा आत्मनिर्भर, होंगे पूरे हर सपने जब
साथ चलेगी आधी आबादी।
आधे आसमान की पूरी उड़ान में ही छिपी खुशियों
की हर चाभी।
तू बस आगे बढ़ के ठान ले तो कदमों पर तेरे है
कामयाबी।
स्वतंत्रता, संस्कृति, सम्मान, शक्ति सब तुझसे ही है।
वो आत्मविश्वासी नारी तू नारायणी।।।

संयुक्त रूप से महिला के नाम आवास देने की पहल पीएम आवास योजना में की गई है।

मिले, इसके लिए केंद्र सरकार ने शारदा एक्ट- 1978 में बदलाव के लिए एक टास्क फोर्स गठित किया है। जिसका काम विवाह की न्यूनतम उम्र क्या हो इसका निर्धारण करना है। अभी लड़कियों के विवाह के लिए 18 वर्ष न्यूनतम आयु का कानून है। हिंसा पीड़ित महिलाओं को राहत देने के मकसद से सरकार ने हाल ही में मेडकल टर्मिनेशन प्रीगनेंसी एक्ट को मंजूरी दी है जिसमें गर्भपात के लिए समय सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया है। मातृत्व अवकाश की सीमा भी 12 बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है। सामाजिक वर्जनाओं को तोड़ने की दिशा में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले से सैनेटरी पैड का जिक्र किया। 24 अक्टूबर को अपने 'मन की बात' कार्यक्रम में महिला शक्ति की बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "सयुंक्त राष्ट्र का प्रभाव और उसकी शक्ति बढ़ाने में, भारत की नारी शक्ति ने, बड़ी भूमिका निभाई है। 1947-48 में जब मानवाधिकारों का वैश्विक घोषणापत्र तैयार हो रहा था तो उसमें लिखा जा रहा था "All Men are Created Equal". लेकिन भारत की एक प्रतिनिध ने इस पर आपत्ति जताई और फिर इसमें लिखा गया - "All Human Beings are Created Equal". ये बात Gender Equality की भारत की सदियों पुरानी परंपरा के अनुरूप थी। वो प्रतिनिधि थीं, हंसा मेहता।"

निश्चित तौर से आज महिलाएं स्वतंत्र है, आर्थिक रूप से सशक्त है, दृढ़ संकल्प से लैस है, सुरक्षा का भाव है और हर क्षेत्र में बराबरी के साथ अपनी प्रतिभा व हुनर की क्षमता दिखाने का साहस कर पा रही हैं तो उसकी बड़ी वजह दशकों से चली आ रही लड़की या महिला को कमतर मानने की सोच में आया बदलाव है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निरंतर कदम उठाए हैं। ऐसे में यह समाज की भी जिम्मेदारी है कि वह संकल्प ले कि एकजुटता के साथ महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा व अपराध को खत्म करेंगे।

7वां संविधान दिवस

संविधान की नींव में नारी सशक्तीकरण की आवाज

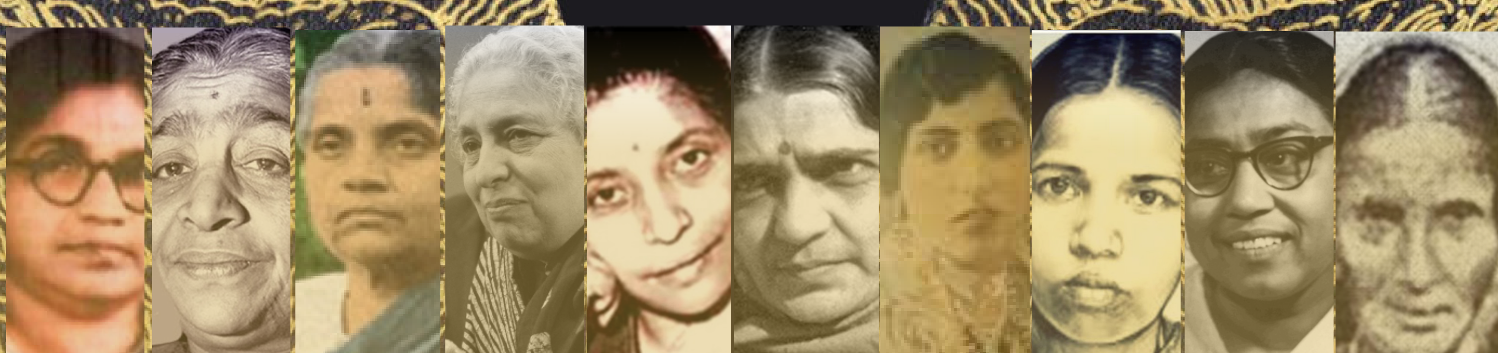

भारत की आजादी से लेकर गणतंत्र तक की यात्रा में ऐसी कई तारीखें हैं, जिन्हें मील के पत्थर के रूप में हमेशा याद किया जाता है। जैसे 26 जनवरी 1950...जब गणतांत्रिक देश के रूप में भारत की प्राण प्रतिष्ठा हुई। लेकिन कुछ तारीखें ऐसी भी हैं, जो इस ऐतिहासिक यात्रा की नींव का पत्थर तो बनीं, पर उन्हें कहीं बिसरा दिया गया। ऐसी ही एक तारीख है 26 नवंबर 1949, यह वो ऐतिहासिक दिन है जब 2 साल 11 महीने और 18 दिन की मेहनत के बाद हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया था। 26 जनवरी का असल महत्व 26 नवंबर में ही निहित है। इस ऐतिहासिक दिन का महत्व स्वीकार किया गया 2015 में, जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 नवंबर को हर वर्ष संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की। इस वर्ष हम संविधान दिवस की 7वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। ऐसे में अमृत महोत्सव की श्रृंखला में जानिए भारत की संविधान सभा में देश की आधी आबादी का नेतृत्व करने वाली उन महिलाओं के बारे में, जिनका अथक परिश्रम हमारे संविधान की नींव में शामिल है...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 नवंबर 2015 को लोकसभा में संविधान का महत्व बताते हुए अपने भाषण में कहा था, "सरकार का एक ही धर्म होता है- भारत प्रथम। सरकार का एक ही धर्मग्रंथ होता है - भारत का संविधान। देश संविधान से ही चलेगा। संविधान से ही चलना चाहिए और संविधान की ताकत से ही देश को ताकत मिल सकती है।" प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहे ये शब्द दर्शाता है कि भारत का संविधान सरकार का धर्मग्रंथ है। यही कारण है कि जिस दिन भारतीयता के धर्मग्रंथ को अंगीकृत किया गया था अब उस दिन संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की गई है। यह दिवस मनाने का यह कतई मतलब नहीं है कि 26 नवंबर को उजागर करके 26 जनवरी के महत्व को कम किया जाए बल्कि इसका उद्देश्य यह है कि वर्तमान के साथ-साथ भविष्य में जिस पीढ़ी के हाथ में देश की बागडोर हो वो हमारे देश को जाने, समझे, सीखे और नए भारत के निर्माण में अपना योगदान दे। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद यह दिवस मनाने की शुरुआत की। इससे पहले वो गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहते हुए साल 2009 में ही संविधान दिवस मनाने की शुरुआत कर चुके थे। हालांकि, जब वे प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भीमराव आंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश में संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की। जब संविधान का निर्माण हुआ उस समय दुनिया के कई देशों में महिलाओं को बुनियादी अधिकार भी हासिल नहीं थे लेकिन भारत की संविधान सभा में 15 महिलाओं को शामिल किया गया था। आजादी के अमृत महोत्सव में इस बार कहानी ऐसी ही महिला नायिकाओं की जो ना केवल संविधान सभा में शामिल थीं बल्कि संविधान निर्माण में पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिला कर अहम योगदान दिया था।

संविधान सभा में शामिल महिलाएं-

भारत के पहले संविधान सभा में 15 महिलाएं थी और उन्होंने संविधान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। उन महिलाओं के नाम हैं-

● एनी मैसकरीन ● विजय लक्ष्मी पंडित ● कमला चौधरी ● हंसा जीवराज मेहता ● सरोजिनी नायडू ● सुचेता कृपलानी ● बेगम अयाज रसूल ● राजकुमारी अमृत कौर ● पूर्णिमा बनर्जी ● रेणुका रे ● अम्मू स्वामीनाथन ● दुर्गाबाई देशमुख ● लीला रॉय ● मालती चौधरी ● दक्षिणयाणी वेलायुधन।

राजकुमारी अमृत कौर के प्रयासों से संभव हो सका था दिल्ली का एम्स

जन्म - 2 फरवरी 1889, मृत्यु - 6 फरवरी 1964

कपूरथला के राजा हरनाम सिंह की बेटी राजकुमारी अमृत कौर ऑक्सफोर्ड से उच्च शिक्षा प्राप्त कर जब 1918 में भारत लौटीं तो उन्होंने ठान लिया कि वह राजनीति में आकर रहेंगी। हालांकि, उनके माता-पिता नहीं चाहते थे कि वह राजनीति में आए लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को कभी रोका नहीं। धीरे-धीरे वह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गईं और बाद के वर्षों में वह 16 वर्ष तक महात्मा गांधी की सचिव रहने के साथ सबसे करीबी लोगों में शुमार रहीं। महात्मा गांधी की कट्टर समर्थक होने के नाते उन्होंने 'नमक आंदोलन' और 'भारत छोड़ो आंदोलन' में हिस्सा लिया, दोनों बार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 2 फरवरी 1889 को जन्मीं अमृत कौर ने देश में कुप्रथाओं के खिलाफ भी निर्णायक लड़ाई लड़ी थी। बच्चों को अधिक मजबूत और अनुशासित बनाने के लिए उन्होंने स्कूली खेलों की शुरुआत करने पर जोर दिया तो नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया की स्थापना करके अपने इरादों को आकार देना शुरू किया था। इतना ही नहीं उन्होंने पर्दा प्रथा, बाल विवाह और देवदासी जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। जब भारत में संविधान सभा का गठन हुआ तो उसमें भी राजकुमारी अमृत कौर ने एक सदस्य के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत की आजादी के बाद उन्हें देश का स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया और वह 10 साल तक इस पद पर रहीं। उन्होंने एम्स की स्थापना के लिए जी तोड़ प्रयास किया और न्यूजीलैंड, जर्मनी, अमेरिका जैसे कई देशों से वित्तीय सहायता प्राप्त करके अंततः देश की सेहत सुधारने का इंतजाम किया। उन्होंने शिमला में पैतृक मकान मैनरविल भी एम्स को दान कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार राजकुमारी अमृत कौर के दिखाए रास्ते पर चल कर आज देश के कई हिस्सों में एम्स की स्थापना कर रही है और देश में स्वास्थ्य ढांचा को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। साथ ही नागरिकों के हित में आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं भी सफलतापूर्वक चला रही है।

टाइम पत्रिका ने पिछले शताब्दी की दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में राजकुमारी अमृत कौर को शामिल किया है।

संविधान सभा में महिला अधिकारों को अम्मू ने किया था बुलंद

जन्म - 22 अप्रैल 1894, मृत्यु - 4 जुलाई 1978

संविधान सभा की हर बैठक में उपस्थित रहने और हर बहस में बढ़-चढ़ कर भाग लेने वाली अम्मू स्वामीनाथन महिलाओं के अधिकार, उनकी समानता और लैंगिक न्याय की जबर्दस्त पक्षधर थीं। संविधान सभा की वह एक ऐसी सदस्य थीं जिन्होंने महिलाओं को समान कानूनी अधिकार दिलवाने के लिए डॉ. आंबेडकर के अथक प्रयासों के साथ खुद को पूरी ताकत के साथ जोड़ा। यही कारण है कि जब संविधान सभा के प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी, तब अम्मू स्वामीनाथन ने कहा था कि बाहरी लोग कहते हैं कि भारतीय महिलाओं को संविधान का अधिकार नहीं दिया जाता, लेकिन अब हम कह सकते हैं कि भारतीयों ने अपना संविधान खुद बनाया है जिसमें महिलाओं को बराबर का हक दिया गया है। केरल राज्य के पलक्कड़ में 22 अप्रैल 1894 को जन्मी अम्मू स्वामीनाथन साल 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बनी थीं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी अम्मू का अविस्मरणीय योगदान रहा है। वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी की अनुयायी बन गई थीं और मां भारती को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करने के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई में हमेशा आगे रहीं। वह साल 1952 में लोकसभा के लिए और साल 1954 में राज्यसभा के लिए चुनी गईं। ऐसा माना जाता है कि वह खुद कभी स्कूल नहीं गईं, लेकिन वह महिला शिक्षा की अहमियत को बखूबी समझती थी। यही कारण है कि उन्होंने महिला शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अहम योगदान दिया। आज अम्मू के दिखाए रास्ते पर ही चल कर भारत सरकार महिलाओं को समानता का हक देने के लिए प्रयासरत है और बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रम चला रही है। उन्होंने भारत स्काउट्स एंड गाइड (1960-65) और सेंसर बोर्ड की भी अध्यक्षता की थी। 4 जुलाई 1978 को उनका निधन हो गया।

अम्मू स्वामीनाथन खुद कभी स्कूल नहीं गईं, लेकिन वह महिला शिक्षा की अहमियत को बखूबी समझती थी।

संविधान सभा में लीला रॉय ने निभाई अहम भूमिका

जन्म: 2 अक्टूबर 1900, मृत्यु : 11 जून 1970

महिलाओं को राजनीति में आने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करने वाली लीला रॉय महिला अधिकारों की बहुत बड़ी हिमायती थीं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक बहादुर सिपाही लीला रॉय का जन्म 2 अक्टूबर 1900 को असम में हुआ था और वह सुभाष चंद्र बोस की करीबी सहयोगी थीं। उनका नाम लीला नाग था, लेकिन अनिल रॉय से शादी करने के कारण वह लीला रॉय के नाम से जानी जाती हैं। बचपन से ही मेधावी रही लीला रॉय ने 1923 में ढाका विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री हासिल की थी। वह नहीं चाहती थी कि महिलाएं आजादी की लड़ाई में पीछे रहे। यही कारण है कि उन्होंने महिलाओं को आंदोलन में शामिल करने के लिए कई प्रयास किए और इसमें वो सफल भी रहीं। माना जाता है कि वह सशस्त्र क्रांति में यकीन रखती थीं और बम बनाना भी जानती थीं। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया जिसके कारण अंग्रेजों ने उन्हें 6 साल तक जेल में रखा। वह संविधान सभा के लिए चुनी जाने वाली बंगाल की पहली महिला थीं हालांकि, उन्होंने विभाजन के विरोध में संविधान सभा छोड़ दी थी। उन्होंने खुद को लड़कियों के लिए शिक्षा के अधिकार दिलाने के लिए झोंक दिया और ढाका में गर्ल्स स्कूल की शुरुआत की। लड़कियों को कौशल सीखने के लिए प्रोत्साहित किया और व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का प्रयास किया। इतना ही नहीं उन्होंने लड़कियों को खुद का बचाव करने के लिए मार्शल आर्ट सीखने की आवश्यकता पर जोर दिया और महिलाओं के लिए कई स्कूल और संस्थान स्थापित किए। लीला रॉय जीवन भर सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में लगी रहीं लेकिन महिलाओं की शिक्षा और उनके उत्थान के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान दिया।

साल 1931 में लीला रॉय ने 'जयश्री' नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया, जिसका संपादन और प्रबंधन महिलाओं ने किया।

संविधान सभा की सदस्य रहीं कमला स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई बार गईं जेल

जन्म: 22 फरवरी 1908, मृत्यु : 15 अक्टूबर 1970

आजादी के संघर्ष काल में जब महिला साहित्यकारों का जिक्र होता है तब स्वतंत्रता सेनानी एवं राष्ट्रवादी महिला कमला चौधरी का चेहरा सहज ही जेहन में उभर आता है। लखनऊ के प्रतिष्ठित परिवार में 22 फरवरी 1908 को जन्मी कमला चौधरी एक ऐसी रचनाकार थीं जिन्होंने सभी ख्यातिलब्ध साहित्यकारों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। इतना ही नहीं उन्होंने महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए सामाजिक-राजनीतिक और सांस्कृतिक स्तर पर प्रयास किया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के चलते वे जवाहर लाल नेहरू सुचेता कृपलानी जैसे राजनेताओं के संपर्क में रहीं और कई बार जेल गईं। वह महात्मा गांधी से भी जुड़ी हुई थी और उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी सक्रियता से हिस्सा लिया। महात्मा गांधी के आजादी के आंदोलन से प्रभावित होकर महिलाओं को जोड़ने के लिए उन्होंने चरखा समितियों का गठन किया था और वह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सदस्य भी रहीं। संविधान निर्माण के लिए गठित सभा में देश भर से चुनी गई 15 महिलाओं में शामिल रहीं कमला चौधरी जीवनपर्यंत साहित्य और राजनीति के माध्यम से महिलाओं के उत्थान के लिए सक्रिय रहीं। इतना ही नहीं, वह उत्तर प्रदेश की संसदीय सीट हापुड़ से 1962 में सांसद चुनी गई थीं। कमला चौधरी का 15 अक्टूबर 1970 को निधन हो गया।

कमला चौधरी ने साहित्यिक क्षेत्र में सक्रियता के साथ स्वाधीनता संग्राम में भी हिस्सा लिया।

वंचितों के उत्थान के लिए जीवन भर समर्पित रहीं मालती चौधरी

जन्म: 26 जुलाई 1904, मृत्यु : 15 मार्च 1998

स्वतंत्रता आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक सक्रिय सदस्य मालती चौधरी ने न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया था, बल्कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समेत वंचित समूहों के उत्थान के लिए जीवन भर संघर्षरत रहते हुए बेहतर कार्य किया था। 26 जुलाई 1904 को जन्मी मालती चौधरी 16 साल की उम्र में पढ़ाई के लिए 1921 में शांति-निकेतन गई थीं जहां वह विश्व भारती में भर्ती हुई थीं। मालती चौधरी ने महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए नमक सत्याग्रह में भाग लिया था और एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में अपना दमखम दिखाया था। वह अपने पति नाबकृष्ण चौधरी के साथ जेल गईं थी जो बाद में ओडिशा के मुख्यमंत्री बने। यही कारण है कि उनकी अपराजेय सक्रियता को देखते हुए महात्मा गांधी ने उनका नाम 'तूफानी' रखा दिया था और रवीन्द्रनाथ ठाकुर उन्हें प्यार से मीनू बुलाते थे। वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई बार जेल गईं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्होंने कांग्रेस समाजवादी कर्म संघ की स्थापना की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने ओडिशा में कमजोर समुदायों के उत्थान के लिए बाजीराव छात्रावास जैसे कई संगठनों की स्थापना की। मालती को 1948 में संविधान सभा के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में चुना गया था। स्वतंत्रता और गणतंत्र प्राप्त होने के बाद भी वह सामाजिक जीवन में लगातार सक्रिय रही और माना जाता है कि उन्होंने 1971 में आपातकाल की घोषणा के खिलाफ प्रदर्शन करके असंतोष की सक्रिय आवाज को बनाए रखा था। 15 मार्च 1998 को 93 साल की उम्र में उनका निधन हो गया।

मालती चौधरी का जन्म पूर्वी बंगाल में हुआ था जो इस समय वर्तमान में बांग्लादेश में आता है।

साल 2010 में संविधान बनने के 60 साल पूरा होने पर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथी पर संविधान की प्रति रख कर शोभा यात्रा निकाली थी। इस यात्रा में मुख्यमंत्री खुद हाथी के आगे पैदल चले थे।

संविधान दिवस : विशेष पहचान देने की पहल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर संविधान की महत्ता को रेखांकित करते रहे हैं और उन्होंने समय-समय पर नागरिकों एवं प्रशासकों को अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों के निर्वहन के प्रति जिम्मेदार बनने का आह्वान किया है। प्रस्तुत है संविधान की महत्ता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के चुनिंदा अंश -

- **संविधान की भावना के साथ जुड़े-** यह हम सब का दायित्व है कि नागरिक, शासन व्यवस्था, सरकार के बीच तालमेल बिठाने का सबसे बड़ा अगर कोई स्रोत है तो वह है हमारा संविधान।
- **संविधान की व्यापकता-** हमारे संविधान की पहचान सभी के लिए समानता और सभी के प्रति संवेदनशीलता है। यह गरीब हो या दलित, पिछड़ा हो या वंचित, आदिवासी हो या महिला सभी के मूलभूत अधिकारों की रक्षा करता है।
- **कर्तव्य भावना की प्रेरणा -** जनता के साथ संवाद करते समय हम कर्तव्यों की बात करना ना भूलें। हमारा संविधान हम भारत के लोग से शुरु होता है। हम भारत के लोग ही इसकी ताकत हैं। मैं जो कुछ हूं, वो समाज के लिए हूं, देश के लिए हूं। यही कर्तव्य भाव हमारी प्रेरणा का स्रोत है। ●

आजादी के 75 वर्ष पर आसियान देशों के साथ मित्रता पर्व मनाएगा भारत

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत हमेशा मुक्त, समावेशी और खुली समुद्री व्यापार व्यवस्था का हिमायती रहा है, यही कारण है कि हाल के वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत और आसियान देशों के बीच आपसी संबंधों को हमेशा वरीयता दी है। भारत-आसियान 18वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने इन संबंधों को भारत के लिहाज से बेहद महत्वूर्ण बताया तो 16वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में बहुपक्षवाद, नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय कानून और सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के साझा मूल्यों के सम्मान की प्रतिबद्धता जताई

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भौगोलिक सामरिक स्थिरता का लक्ष्य, हाल के वर्षों में भारत और आसियान देशों के बीच सामरिक सहयोग के तमाम आयामों का केंद्र बिंदु बन गया है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ भारत आसियान देशों के साथ अपने संबंधों को लगातार मजबूत कर रहा है। 70 करोड़ से अधिक आबादी और करीब 250 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की जीडीपी के साथ दक्षिण पूर्व एशिया के 10 सदस्य देशों का संगठन आसियान न केवल भारत के लिए महत्वूपर्ण है, बल्कि अपनी स्थापना के बाद से ही हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत के मजबूत रणनीतिक और साझेदार भी रहा है। वर्ष 2022 में जब भारत अपनी आजादी के 75 साल पूरे करेगा, भारत-आसियान संबंधों के भी 30 वर्ष पूरे होंगे। आसियान देशों के साथ 28 अक्टूबर को आयोजित शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत-आसियान मित्रता वर्ष के रूप में रूप मनाने की घोषणा की। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "इतिहास गवाह है कि भारत और आसियान के बीच हजारों साल से जीवंत संबंध रहे हैं। इनकी झलक हमारे साझा मूल्य, परम्पराएं, भाषाएं, ग्रन्थ, वास्तुकला, संस्कृति, खान-पान, हर जगह पर दिखते हैं। इसीलिए आसियान की एकता भारत की प्राथमिकता रही है।" इससे एक दिन पहले ही 27 अक्टूबर को पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "भारत हमेशा से एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र में आसियान केंद्रीयता के सिद्धांत पर फोकस करने को वरीयता देता है।"

गणतंत्र दिवस पर भी भारत ने की थी आसियान देशों की मेजबानी

आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन 10 अहम देशों का एक समूह है। 1967 में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने इस संगठन की शुरुआत की थी। बाद में इसके सदस्य देशों में ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम को शामिल किया गया। कई अहम पैमानों पर भारत और आसियान की सोच भी एकसमान है। क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के साथ ही खुली, संतुलित और समावेशी अवधारणा पर भी दोनों एकमत हैं। लुक ईस्ट की नीति के तहत भारत ने आसियान देशों के साथ अपने संबंधों को संवारा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्ट ईस्ट की पॉलिसी के साथ आपसी संबंधों को नया स्वरूप देते हुए 2017 में गणतंत्र दिवस परेड के लिए मुख्य अतिथि के रूप में सभी आसियान देशों को आमंत्रित कर इन संबंधों को नया विस्तार दिया था। इसके साथ ही 2019 में इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव की शुरुआत कर भारत ने इन संबंधों में मील का नया पत्थर रखा। आसियान जहां दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों का संगठन है तो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन हिंद-प्रशांत क्षेत्र में प्रमुख नेताओं के नेतृत्व वाला मंच है। इसमें 10 आसियान सदस्य देशों के अलावा भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस शामिल हैं। 2005 में अपनी स्थापना के बाद से, इसने पूर्वी एशिया के रणनीतिक और भू-राजनीतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ●

उत्तर प्रदेश को सेहत के साथ उड़ान का डबल डोज

जनसंख्या के लिहाज से देश का सबसे बड़ा प्रदेश, उत्तर प्रदेश हमेशा से प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकताओं में शामिल रहा है। यही कारण है 20 अक्टूबर को बौद्ध पर्यटन सर्किट के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से के तौर पर उन्होंने कुशीनगर में अंतरराष्ट्रीय हवाई की शुरुआत कर उत्तर प्रदेश को विकास का नया 'रनवे' सौंपा तो 25 अक्टूबर को सिद्धार्थ नगर से 9 नए मेडिकल कॉलेजों की शुरुआत कर पूर्वांचल को स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भता का नया रोडमैप सौंपा। पूरे देश में ब्लॉक से शहरों तक स्वास्थ्य ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव की पहल के तौर 'आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत' योजना की शुरुआत भी प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से की...

सर्वोत्तम स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी देश के लिए दो सबसे बुनियादी जरूरतें हैं। यह आम जन के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता का ही नतीजा है कि देश के स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की सूरत बदलने का जो बीड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया है वो इस कोविड जैसी महामारी के बीच भी न रुका न थमा, बल्कि और ज्यादा तेज रफ्तार से आगे बढ़ चला है। फिर बात चाहे 107 लाख करोड़ रुपये के गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के साथ देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास की नई इबारत लिखने की हो या फिर 137 फीसदी की बजट बढ़ोतरी के साथ पूरा स्वास्थ्य ढांचा बदलने की। केंद्र सरकार दोनों ही सेक्टर में जबरदस्त सुधार की पहल के साथ आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, "एक समय था, जब आजादी के बाद से 2014 तक देश के मेडिकल कॉलेजों में करीब

> अगले 10-12 वर्षों में, देश को कई डॉक्टर प्राप्त होने जा रहे हैं जो आजादी के बाद के 70 वर्षों में मेडिकल कॉलेजों से स्नातक होने वाले डॉक्टरों की संख्या से अधिक होंगे। यूपी में जिस तेजी से नए मेडिकल कॉलेज शुरू हो रहे हैं, उसका सकारात्मक असर मेडिकल सीटों और डॉक्टरों की संख्या पर पड़ेगा। सीटों की संख्या अधिक होने के कारण अब गरीब माता-पिता के बच्चे भी डॉक्टर बनने का सपना देख सकते हैं और उसे पूरा कर सकते हैं।
>
> – नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

90 हजार सीटें हुआ करती थीं। बीते 7 साल में ही हमने 60 हजार से ज्यादा नई सीटें जोड़ी हैं। मेरी इच्छा है कि देश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो।"

अब स्वास्थ्य के मामले में आत्मनिर्भर होगा उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल

28 जिलों के साथ उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होने के बावजूद पूर्वांचल का इलाका विकास के मामले में कहीं पिछड़ा रह गया था। सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "यूपी और पूर्वांचल में आस्था, अध्यात्म और सामाजिक जीवन से जुड़ी बहुत विस्तृत विरासत है। इसी विरासत को स्वस्थ, सक्षम, और समृद्ध उत्तर प्रदेश के भविष्य के साथ भी जोड़ा जा रहा है। जिस पूर्वांचल को पहले की सरकारों ने, बीमारियों से जूझने के लिए छोड़ दिया था, वही अब पूर्वी भारत का मेडिकल हब बनेगा, अब देश को बीमारियों से बचाने वाले अनेक डॉक्टर ये धरती देश को डॉक्टर देने वाली है। जिस पूर्वांचल की छवि पिछली सरकारों ने खराब कर दी थी, जिस पूर्वांचल को दिमागी बुखार से हुई दुखद मौतों की वजह से बदनाम कर दिया गया था, वही पूर्वांचल, वही उत्तर प्रदेश, पूर्वी भारत को सेहत का नया उजाला देने वाला है।"

प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत यानी शहरों से ब्लॉक तक स्वास्थ्य ढांचे को बदलने की शुरुआत

प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी 2021 को पेश किए गए बजट में की थी। इसके तहत देश में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर फोकस किया जा रहा है। 5 वर्षों में 64,180 करोड़ रुपये के जरिए हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए जाएंगे। 25 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से इस योजना की शुरुआत करते हुए कहा, "आजादी के बाद आरोग्य और स्वास्थ्य सुविधा पर ध्यान नहीं

9 मेडिकल कॉलेजों में 2,500 बेड मिलेंगे

5 हजार से अधिक डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए रोजगार के अवसर

दिया गया जितनी जरूरत थी। हेल्थ केयर सिस्टम में कमी की वजह से गरीब और मध्यम वर्ग चिंतित रहता था। योजना इसी कमी के लिए दूर का समाधान है। महामारी से निबटने में हम तैयार हों, सक्षम हों। इसके लिए हेल्थ सिस्टम को तैयार किया जा रहा है। लक्ष्य है कि गांव से ब्लॉक, जिला, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर तक क्रिटिकल हेल्थ केयर मजबूत हो। मिशन के तीन पहलू हैं। डायग्नोमस्टिक सिस्टम के तहत हेल्थ और वेलनेस सिस्टम के साथ बीमारी की पहचान फ्री में होगी। समय पर बीमारी पता चलेगी तो गंभीर होने की आशंका कम होगी। उसके इलाज के लिए 600 से अधिक जिलों के क्रिटिकल केयर के लिए बेड तैयार किए जाएंगे। सवा सौ जिलों में रेफरल की सेवा दी जाएगी। ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग और अस्पताल में सुविधा बढ़ेगी। सर्जरी से जुड़े नेटवर्क चौबीसों घंटे के लिए तैयार होंगे। रोगों की जांच से जुड़ा टेस्टिंग नेटवर्क दूसरा बिंदु है। जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। 730 जिलों में इंटीग्रेटेट सिस्टम डेवलप होगा। इस नेटवर्क को और सशक्त किया जाएगा। तीसरा पहलू, रिसर्च संस्थानों को सशक्त बनाने का है। इसके माध्यम से देश के कोने-कोने में इलाज से लेकर इको सिस्टम विकसित किया जाएगा।"

वाराणसी में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत पर प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने के लिए QR कोड स्कैन करें।

पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना से बदलेगा देश का स्वास्थ्य ढ़ांचा

- विशेष फोकस वाले 10 राज्यों में 17,788 ग्रामीण स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों के लिए सहायता। सभी राज्यों में 11,024 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की स्थापना।
- सभी जिलों में एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं और विशेष फोकस वाले 11 राज्यों के 3382 ब्लॉक में सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना।
- देश के 602 जिलों और 12 केंद्रीय संस्थानों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक की स्थापना। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) की 5 क्षेत्रीय शाखाओं और 20 महानगरीय स्वास्थ्य निगरानी इकाइयों को मजबूत करना।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं को जोड़ने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल का विस्तार। 17 नई सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों को शुरू करना
- 33 मौजूदा सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों को मजबूत करना, जो कि 32 हवाई अड्डों, 11 बंदरगाहों और 7 लैंडक्रॉसिंग पर स्थित हैं। 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर और 2 मोबाइल अस्पतालों की स्थापना।

इस योजना से यह फायदा होगा

आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का लक्ष्य ब्लॉक, जिला, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर आईटी आधारित रोग निगरानी प्रणाली विकसित करना है। जिसके तहत इन क्षेत्रों की प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क विकसित करना है। इसके लिए स्वास्थ्य इकाइयों को मजबूत करके, बीमारी का प्रभावी ढंग से पता लगाने, जांच करने, रोग के प्रसार को रोकने और मुकाबला करने के लिए तैयार करना है। साथ ही इसके जरिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएचपी), 2017 की सिफारिशों के अनुसार समयबद्ध तरीके से 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च को जीडीपी के 1.15 % से बढ़ाकर 2.5% करने का लक्ष्य है।

602 जिलों में क्रिटिकल केयर यूनिट

स्वस्थ भारत के लिये चार-स्तरीय रणनीति

स्वच्छ भारत अभियान, योग, गर्भवती महिलाओं बच्चों की समय पर देखभाल एवं उपचार जैसे उपायों सहित बीमारी की रोकथाम व स्वास्थ्य कल्याण को बढ़ावा देना।

समाज के वंचित वर्ग के लोगों को सस्ता और प्रभावी इलाज मुहैया कराना।

स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की गुणवत्ता को बढ़ाना।

बाधाओं को दूर करने के लिये एक मिशन मोड पर काम करना, जैसे- मिशन इंद्रधनुष, जिसे देश के जनजातीय और दूरदराज के क्षेत्रों तक बढ़ाया गया है।

वाराणसी: 5,200 करोड़ रु. की सौगात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत अभियान की शुरुआत की तो वाराणसी को करीब 5,200 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की सौगात दी। इनमें बुनियादी सुविधाओं, पर्यटन, कृषि से जुड़ी तकरीबन 28 पूरी हो चुकी परियोजनाओं हैं। इससे प्रयागराज, लखनऊ, बिहार तक कारोबार को गति मिलेगी।

उत्तर प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने के लिए QR कोड स्कैन करें।

कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की शुरुआत

सपनों की उड़ान का टेक-ऑफ

जब सबका है आसमां तो उड़ान भी सबकी क्यों न हो। जब हौसला है आसमानी तो यह जहां भी मुट्ठी में क्यों न हो। लंबे समय तक विकास से वंचित उत्तर प्रदेश अब इस नई सोच के साथ देश-दुनिया में नई पहचान बना रहा है तो केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण और जन सुविधाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की दिशा में लिख रहा है नई इबारत, जिसकी मिसाल बनी है बौद्ध सर्किट के तहत आने वाले कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की रिकॉर्ड समय सीमा में हुई शुरुआत

भविष्योन्मुखी बुनियादी ढांचे का निर्माण अब देश की प्राथमिकताओं में शामिल है। देश का हर हिस्सा, हर क्षेत्र आधुनिक और मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी से जुड़े इस संकल्प के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण को आजादी के अमृत काल में गति देने के लिए पीएम गतिशक्ति की शुरुआत की गई है, ताकि समन्वय के साथ निर्बाध विकास संभव हो सके। इसी सोच का उम्दा उदाहरण बन देश की विकास यात्रा में अहम भागीदार के रूप में उड्डयन क्षेत्र में गत वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति की है। देश में जहां आजादी से 2014 तक सिर्फ 74 हवाई अड्डे संचालित थे, वहीं बीते सात वर्षों में 62 नए हवाई अड्डे संचालित किए गए हैं। उड़ान योजना के तहत आज टीयर-3 शहरों में रहने वाला सामान्य जन भी हवाई यात्रा से देश-विदेश से जुड़ गया है।

सरकार के इन प्रयासों से विशेषकर उत्तर प्रदेश लाभान्वित हुआ है। यहां से उड़ान योजना के अंतर्गत आगरा, हिंडन, कानपुर, बरेली और प्रयागराज हवाई अड्डे सेवा दे रहे हैं। कुछ ही महीनों में अलीगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद, मयुरपुर तथा श्रावस्ती में 5 और हवाई अड्डे तैयार हो जाएंगे।

केंद्र और राज्य सरकार विश्व स्तरीय सड़क, रेल और हवाई संपर्क द्वारा बौद्ध सर्किट के समग्र विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में कुशीनगर की पावनभूमि जहां पर 2,500 साल पहले भगवान बुद्ध ने परिनिर्वाण प्राप्त किया, वहां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया गया है। इससे देश और विदेश के विशेष रूप से दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के बौद्ध धर्मावलंबी और पर्यटक सुगमता से कुशीनगर की यात्रा कर सकेंगे। जिन्हें पहले सीधी अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी के अभाव में देश के विभिन्न अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से होकर कुशीनगर आना पड़ता था। कुशीनगर हवाई अड्डे के संचालन से कुशीनगर स्थिति महापरिनिर्वाण मंदिर के साथ-साथ इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों जैसे- सारनाथ, श्रावस्ती, संकिसा और लुम्बिनी जाना भी पर्यटकों के लिए आसान हो जाएगा।

- कुशीनगर हवाई अड्डे में अंतरराष्ट्रीय संचालन के लिए 3600 वर्ग मीटर के नए टर्मिनल भवन का निर्माण मात्र 5 महीनों के रिकॉर्ड समय में किया गया है।
- इस टर्मिनल में एक समय में 300 यात्रियों के प्रबंधन की क्षमता है। इस हवाई अड्डे का रन-वे एयरबस-321 एवं बोईंग-737 और अन्य प्रकार के विमानों के परिचालन के लिए सक्षम है।
- हवाई अड्डे के विकास से पर्यटन और हॉस्पिटिलटी सेक्टर को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही आसपास के जिलों की 2 करोड़ से अधिक आबादी को हवाई मार्ग से जुड़ने का अवसर मिलेगा।
- इससे यहां निवेश बढ़ेगा, रोजगार और कारोबार के अवसर पैदा होंगे। साथ ही, स्थानीय उत्पादों का निर्यात संभव हो पाएगा।
- कुशीनगर हवाई अड्डा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 से मात्र 5 किमी एवं रेलवे स्टेशन पडरौना से 18 किमी की दूरी पर स्थित है। मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी से इसके विकास को नई गति मिलेगी।
- कैबिनेट की मंजूरी के एक साल के भीतर इसका उद्घाटन हुआ है। दक्षिण एशियाई देशों के साथ सीधा हवाई संपर्क।
- लुम्बिनी, सारनाथ और गया में तीर्थ स्थल समेत बौद्ध सर्किट का विकास। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों जगहों पर पर्यटकों के आगमन में वृद्धि होगी। राजकीय मेडिकल कॉलेज सहित 12 परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई।

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन पर प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने के लिए QR कोड स्कैन करें।

अब 9 दिन चले अढ़ाई कोस नहीं कहिए ढाई दिन में चले सौ कोस

दुनिया के सबसे बड़े और मुफ्त के साथ सबसे तेज टीकाकरण अभियान का रिकॉर्ड

भारत में एक मशहूर कहावत है- नौ दिन चले अढ़ाई कोस। एक समय था जब यह कहावत बहुत धीमी रफ्तार के साथ सुस्त सरकारी कार्यशैली का पर्याय बन चुकी थी। लेकिन कोविड जैसी वैश्विक आपदा के बीच भारत की टीकाकरण रफ्तार ने इस कहावत के मायने बदल दिए हैं। जहां एक टीका बनाने में 9-10 साल लगते थे, भारत ने महज नौ महीने में ही दो-दो स्वदेशी वैक्सीन का ईजाद कर दिया और अब 100 करोड़ टीके लगाने का कीर्तिमान स्थापित कर लिया है तो इसकी सबसे बड़ी वजह है- आत्मविश्वास जो किसी भी अभियान का मूल आधार होता है और इस आत्मविश्वास का आधार बना है भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में उसका मौजूदा नेतृत्व जो चुनौतियों और समस्याओं से टकराने में विश्वास रखता है...

कृतम् मे दक्षिणे हस्ते, जयो मे सव्य आहितः।

अथर्ववेद के इस सूत्र का अर्थ है- मेरे दाएं हाथ में कर्म है और बाएं हाथ में विजय। 22 अक्टूबर को राष्ट्र को संबोधित करते हुए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन शब्दों के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की तो कोविड काल की शुरुआत से लेकर 100 करोड़ वैक्सीन डोज के विश्व इतिहास तक पहुंचने की भारत की पूरी यात्रा भी उन्होंने सबके सामने रखी। उन्होंने कहा, "आज कई लोग भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तुलना दुनिया के दूसरे देशों से कर रहे हैं। भारत ने जिस तेजी से 100 करोड़ का, वन बिलियन का आंकड़ा पार किया है , उसकी सराहना भी हो रही

100 करोड़ टीकाकारण पर प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन सुनने के लिए QR कोड स्कैन करें।

सदी की सबसे बड़ी महामारी के खिलाफ निर्णायक कदम के तौर पर भारत के टीकाकरण की रफ्तार की दुनिया ने की तारीफ।

है। लेकिन, इस विश्लेषण में एक बात अक्सर छूट जाती है कि हमने ये शुरुआत कहां से की है?"

दरअसल, दुनिया के दूसरे बड़े देशों को वैक्सीन पर रिसर्च करने में महारथ हासिल थी और भारत अधिकतर इन देशों की बनाई वैक्सीन पर ही निर्भर रहता था। इसी वजह से जब 100 साल की सबसे बड़ी महामारी आई तो भारत पर सवाल उठने लगे। क्या भारत इस वैश्विक महामारी से लड़ पाएगा? भारत दूसरे देशों से इतनी वैक्सीन खरीदने का पैसा कहां से लाएगा? भारत को वैक्सीन कब मिलेगी? भारत के लोगों को वैक्सीन मिलेगी भी या नहीं? क्या भारत इतने लोगों को टीका लगा पाएगा कि महामारी को फैलने से रोक सके? कई सवाल थे लेकिन 21 अक्टूबर को भारत ने सबसे कम समय में 100 करोड़ वैक्सीन डोज के साथ हर सवाल का जवाब दे दिया। 100 करोड़ वैक्सीन डोज और वो भी मुफ्त। ये केवल एक आंकड़ा नहीं है। ये देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है, इतिहास के नए अध्याय की रचना है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो कठिन लक्ष्य निर्धारित कर, उन्हें हासिल करना जानता है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो अपने संकल्पों की सिद्धि के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करता है। 100 करोड़ वैक्सीन डोज का एक प्रभाव ये भी होगा कि दुनिया अब भारत को कोरोना से ज्यादा सुरक्षित मानेगी। एक फार्मा हब के रूप में भारत को दुनिया में जो स्वीकृति मिली हुई है, उसे और मजबूती मिलेगी। पूरा विश्व आज भारत की इस ताकत को देख रहा है, महसूस कर रहा है।

टीका लगाने के मामले में भारत की रफ्तार का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि यूरोपियन यूनियन, अरब लीग, नाटो, जी-7, आसियान जैसे देशों के रोजान औसत से भारत कहीं आगे है। आज भारत जहां एक दिन में 1 करोड़ से अधिक टीके लगाने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है जबकि जापान को इतने ही डोज लगाने में 8 दिन, अमेरिका को 11 दिन, जर्मनी को 45 दिन, इजरायल को 104 दिन और न्यूजीलैंड को 124 दिन लगते हैं। उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्यों ने भी दुनिया के कई देशों से अधिक औसतन टीके लगाए। यही वजह है कि टीका लगाने के मामले में भी आज भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है।

वैक्सीन निर्माताओं की अहम भूमिका

भारत की इस उपलब्धि में अहम साझेदार के रूप में वो टीका निर्माता भी हैं, जिनकी वजह से यह लक्ष्य पूरा हो पाया है तो साथ ही अब इसके बाद भारत वैक्सीन निर्माण का वैश्विक हब बनने की ओर अग्रसर है। 23 अक्टूबर को प्रधानमंत्री आवास पर देश में कोविड वैक्सीन बनाने वाले इन 7 निर्माताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जिक्र करते हुए कहा, "टीकाकरण अभियान की सफलता को देखते हुए पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने हेतु तैयार रहने के लिए टीका निर्माताओं को लगातार मिलकर काम करना चाहिए।" सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा, "भारत की 100 करोड़ वैक्सीनेशन की उपलब्धि एक मील का पत्थर है। हमारे प्रधानमंत्री के नजरिए और दिशा निर्देश में हमने इसे हासिल किया है। प्रधानमंत्री अपने रास्ते पर डटे रहे, सभी को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। सरकार के साथ इंडस्ट्री ने मिल कर काम किया, इसलिए 100 करोड़ टीकाकरण का आंकड़ा हम प्राप्त कर सके।"

> 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा बहुत बड़ा जरुर है, लेकिन इससे लाखों छोटे-छोटे प्रेरक और गर्व से भर देने वाले अनेक अनुभव, अनेक उदाहरण जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग पत्र लिखकर मुझसे पूछ रहे हैं कि वैक्सीन की शुरुआत के साथ ही कैसे मुझे यह विश्वास हो गया था कि इस अभियान को इतनी बड़ी सफलता मिलेगी ? मुझे ये दृढ़ विश्वास इसलिए था, क्योंकि मैं अपने देश, अपने देश के लोगों की क्षमताओं से भली-भांति परिचित हूं।
>
> – **नरेंद्र मोदी,** प्रधानमंत्री

हेल्थ वर्कर्स से लेकर वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा

देश-दुनिया ने वह तस्वीर देख दांतों तले उंगली दबा ली, जब बाढ़ की भयावहता के बीच बिहार जैसे राज्य ने टीके वाली नाव चलाकर टीकाकरण की राह दिखाई तो दुर्गम पहाड़ियां, सुदूर जनजातीय क्षेत्र, भाषाई-धार्मिक विविधताएं और चुनिंदा अफवाहों के बीच टीकाकरण में भारत ने अभूतपूर्व गति का कीर्तिमान स्थापित कर दिया। विविधता से भरे देश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में जनसंवाद और जनभागीदारी विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का आधार बन गया है, जो इस कोविड जैसी वैश्विक महामारी के खिलाफ जीवन रक्षा और मानव सभ्यता को बचाने का प्रतीक बनकर उभरा है। 100 करोड़ टीके के ऐतिहासिक पल की नींव में भारत के वैज्ञानिक, फ्रंटलाइन वर्कर, हेल्थ वर्कर से लेकर उन सभी लोगों का प्रयास शामिल है, जिनकी वजह से यह मुमकिन हो पाया है। तभी तो खुद प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के राममनोहर लोहिया अस्पताल में 100 करोड़ डोज के ऐतिहासिक पल के समय हेल्थ लाइन वर्कर्स को धन्यवाद दिया तो अपने 'मन की बात' कार्यक्रम में भी ऐसे कई हेल्थ वर्कर के साथ संवाद करते हुए उनकी कहानियां साझा कीं। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के चानी कोराली सेंटर पर तैनात एएनएम पूनम नौटियाल ने प्रधानमंत्री के साथ संवाद में टीकाकरण के बीच उन चुनौतियों का जिक्र किया जिन पर विजय हासिल कर उत्तराखंड 100 फीसदी पहली कोविड वैक्सीन की डोज लेने वाला राज्य बना है। पूनम ने कहा- "बारिश से कभी-कभी सड़क बंद हो जाती थी। वैक्सीनेशन के लिए कई बार नदी पार करनी पड़ी। तराई वाले इलाकों में 8 से 10 किमी रोज चलना पड़ा। बावजूद इन कठिनाइयों के हमने संकल्प लिया था कि एक भी आदमी बचना नहीं चाहिए। घर-घर जाकर लोगों को वैक्सीन दी है। कई लोगों को इसके लिए समझाना तक पड़ा, लेकिन हमने अपना लक्ष्य पूरा कर ही दम लिया।"

अपने एक विशेष लेख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टीकाकरण कार्यक्रम की चुनौतियों का जिक्र करते हुए लिखा- "आज तक केवल कुछ चुनिंदा देशों ने ही अपने स्वयं के टीके विकसित किए हैं। 180 से भी अधिक देश टीकों के लिए जिन उत्पादकों पर निर्भर हैं, वे बेहद सीमित संख्या में हैं। यही नहीं, जहां एक ओर भारत ने 100 करोड़ खुराक का अविश्वसनीय या जादुई आंकड़ा सफलतापूर्वक पार कर लिया है, वहीं दूसरी ओर दर्जनों देश अब भी अपने यहां टीकों की आपूर्ति की बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं! इसका श्रेय भारतीय वैज्ञानिकों और उद्यमियों को दिया जाना चाहिए, जिन्होंने इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनकी उत्कृष्ट प्रतिभा और कड़ी मेहनत की बदौलत ही

दुनिया ने की तारीफ

भारत की इस उपलब्धि पर मालदीव से लेकर श्रीलंका और अमेरिका से इजरायल तक तमाम देशों ने बधाई दी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस ए ग्रीबीसीस ने कहा, "भारत ने कोरोना महामारी के दौर में बिना किसी पक्षपात के इतना बड़ा टीकाकरण लक्ष्य हासिल किया। -इजराल के पीएम नफ्ताली बेनेट ने बधाई देते हुए कहा, "कोविड-19 के खिलाफ भारत के सफल टीकाकरण अभियान का नेतृत्व करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई। उन्होंने कहा कि ये जीवन रक्षक टीके हमें कोविड महामारी के खिलाफ जारी जंग जीतने में मदद करेंगे।" अमेरिका ने कहा, "भारत के सामूहिक प्रयास की यह ऐतिहासिक जीत है। इसने कोरोना की जंग जीतने में एक बड़ी भूमिका निभाई है।"

248 दिन बाद सबसे कम केस, वैक्सीनेशन 106 करोड़ के पार

1 नवंबर को कोविड के 12,514 नए केस दर्ज किए गए हैं। ठीक होने वालों मरीजों का प्रतिशत बढ़कर 98.20% पहुंच चुका है। वहीं वैक्सीनेशन का आंकड़ा 1 नवंबर तक 106 करोड़ के पार पहुंच चुका है। भारत में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1,58,817 है, जो पिछले 248 दिनों में सबसे कम है। वहीं अब तक 60.92 करोड़ से अधिक (60,92,01,294) नमूनों की कोविड जांच की गई है।

106.31 करोड़ से अधिक भारत का टीकाकरण कवरेज

भारत में कोविड से स्वस्थ होने की वर्तमान दर इस समय 98.20% है।

पॉजिटिव दर 0.46 प्रतिशत है। जो मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है

कोविड टीकाकरण	स्वास्थ कर्मी	फ्रंटलाइन वर्कर	18-44 साल	45-59 साल	60 साल+
पहली डोज	1.03 करोड़	1.83 करोड़	41.89 करोड़	17.49 करोड़	10.97 करोड़
दूसरी डोज	92.24 लाख	1.59 करोड़	14.24 करोड़	9.64 करोड़	6.67 करोड़

आंकडे 1 नवंबर 2021 तक।

टीकाकरण में आत्मनिर्भर बनने के बाद अब पूरी दुनिया में सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता के तौर पर नई भूमिका की शुरुआत।

भारत टीकों के मामले में 'आत्मनिर्भर' बन गया है। भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में सिर्फ उत्पादन करना ही काफी नहीं है। इसके लिए अंतिम व्यक्ति तक को टीका लगाने और निर्बाध लॉजिस्टिक्स पर भी फोकस होना चाहिए। इसमें निहित चुनौतियों को समझने के लिए जरा इसकी कल्पना करें कि टीके की एक शीशी को आखिरकार कैसे मंजिल तक पहुंचाया जाता है। पुणे या हैदराबाद स्थित किसी दवा संयंत्र से निकली शीशी को किसी भी राज्य के हब में भेजा जाता है, जहां से इसे जिला हब तक पहुंचाया जाता है।

फिर वहां से इसे टीकाकरण केंद्र तक पहुंचाया जाता है। इसमें विमानों की उड़ानों और ट्रेनों के जरिये हजारों यात्राएं सुनिश्चित करनी पड़ती हैं। टीकों को सुरक्षित रखने के लिए इस पूरी यात्रा के दौरान तापमान को एक खास रेंज में बनाए रखना होता है, जिसकी निगरानी केंद्रीय रूप से की जाती है। इसके लिए एक लाख से भी अधिक शीत-श्रृंखला (कोल्ड-चेन) उपकरणों का उपयोग किया गया। राज्यों को टीकों के वितरण कार्यक्रम की अग्रिम सूचना दी गई थी, ताकि वे अपने अभियान की बेहतर योजना बना सकें और टीके पूर्व-निर्धारित तिथि को ही उन तक सफलतापूर्वक पहुंच सकें। अतः स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह निश्चित रूप से एक अभूतपूर्व प्रयास रहा है।

इन सभी प्रयासों को कोविन के एक मजबूत तकनीकी मंच से जबर्दस्त मदद मिली। इसने यह सुनिश्चित किया कि टीकाकरण अभियान न्यायसंगत, मापनीय, ट्रैक करने योग्य और पारदर्शी बना रहे। इसने यह भी सुनिश्चित किया कि एक गरीब मजदूर अपने गांव में पहली खुराक ले सकता है और उसी टीके की दूसरी खुराक तय समय अंतराल पर उस शहर में ले सकता है, जहां वह काम करता है।"

आज अगर टीकाकरण की रफ्तार में भारत के नए-नए रिकॉर्ड स्थापित हो रहे हैं, तो इसकी वजह है स्वास्थ्य ढांचे की मजबूती के लिए निरंतर किए जा रहे प्रयास। अब भारत की तैयारी ऐसी किसी भी महामारी से जूझने के लिए स्वास्थ्य ढांचे का नया तंत्र विकसित करने में जुट चुका है।●

आतंक को जवाब

अनुच्छेद 370 के खात्मे के साथ कश्मीर घाटी में लाखों लोगों के विकास का रास्ता खुला तो धरती की जन्नत कहा जाने वाला ये इलाका भी अब देश के दूसरे राज्यों की तरह रफ्तार पकड़ने लगा है। वही कश्मीर जो करीब 31 वर्ष पहले पड़ोसी देश के नापाक इरादों के चलते आतंकवाद की राह पर चल पड़ा था, वहीं अब विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। अपने कश्मीर दौरे में गृहमंत्री अमित शाह ने न केवल विकास परियोजनाओं की शुरुआत की, बल्कि देश की धरती से आतंक के आकाओं को कड़ा जवाब भी दिया, फिर चाहे वह आतंकी हमले में शहीद हुए पुलिस कर्मियों के परिवार से मिलना हो या फिर बीएसएफ के जवानों के साथ वक्त बिताना। मंच से बुलेटप्रूफ ग्लास हटाकर उन्होंने कहा- मैं घाटी के युवाओं से दोस्ती करने आया हूं...

जब गृहमंत्री ने हटवाई बुलेटप्रूफ शील्ड, बोले- लोग डर निकाल दें

श्रीनगर में एक जनसभा को संबोधित करने से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने बुलेट प्रूफ ग्लास शील्ड हटवा दी और कहा कि ना उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है और ना ही सिक्युरिटी है। ऐसे ही आपके सामने खड़ा हूं। घाटी के लोग भी अब अपने दिल से डर निकाल दें। आप भारत सरकार और हम पर भरोसा रखिए। अपने संबोधन में गृह मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि वे पाकिस्तान से नहीं, घाटी के लोगों और युवाओं से बातचीत करेंगे। वे घाटी के युवाओं से दोस्ती करेंगे।

किसी भी क्षेत्र में परिवर्तन करना है तो परिवर्तन का वाहक युवा ही हो सकता है। ऐसे में जम्मू कश्मीर जैसे केन्द्र शासित प्रदेश से बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है, जहां की लगभग 70 प्रतिशत आबादी युवा है और जिसकी आयु 35 साल से कम है। जहां पहले कश्मीर से पथराव व हिंसा के समाचार आते थे, वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर का युवा विकास, शिक्षा और रोजगार की बात कर रहा है। यही कारण है कि गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जब अपने चार दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए तो उन्होंने कहा, "अब कोई कितना भी जोर लगा ले, बदलाव की इस बयार को कोई रोक नहीं सकता।" गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के ये शब्द दर्शाते हैं कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस युवा शक्ति के मन में एक आशा जगाकर, इन्हें विकास से जोड़ कर जम्मू-कश्मीर की शांति व विकास का राजदूत बनाने का लक्ष्य है, जिससे कभी भी कोई कश्मीर की शांति में खलल नहीं डाल सकेगा। आज केन्द्र की मोदी सरकार चाहती है कि कश्मीर का युवा पत्थर नहीं पुस्तक उठाए, हथियार नहीं कलपुर्जे के साधन उठाए और अपने जीवन को संवारे। यही कारण है कि अन्यायी धारा 370 को खत्म कर जम्मू कश्मीर की जनता को उनके अधिकार दिए गए। जिसके कारण अब वहां अन्याय समाप्त हो चुका है और कोई भी वहां

शहीदों के परिजन से जवानों के बीच तक एक ही संदेश- बदलाव की बयार कोई रोक नहीं सकता

- गृहमंत्री ने जम्मू में भारत की सीमा के अंतिम गांव मकवाल में जाकर ग्रामवासियों का हाल जाना। साथ ही बीएसएफ के जवानों से भेंट कर उनके साथ कुछ समय बिताया। जम्मू के गुरुद्वारा डिगियाना आश्रम में मत्था टेक कर सभी के लिए खुशहाली और समृद्धि के लिए अरदास की।
- पंचायत लेखा सहायकों, श्रेणी **IV** में नियुक्त होने वाले व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र, पीएम स्वनिधि व तेजस्वनी योजना के लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र और **OTFD** हेतु 500 राइट सर्टिफिकेट प्रदान किए।
- जम्मू में जनसभा को संबोधित किया और विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। जम्मू में आईआईटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया। 210 करोड़ रुपए से बने इस कैंपस में छात्रों की उच्च शिक्षा के साथ-साथ अच्छे छात्रावास, जिम, इंडोर गेम्स जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध है।
- आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हुए सुरक्षाकर्मियों के परिजनों और आतंकी घटनाओं में मारे गए आम नागरिकों के परिजनों से भेंट की। श्रीनगर से शारजाह के लिए अंतरराष्ट्रीय उड़ान का उद्घाटन किया।
- श्रीनगर में सशस्त्र बलों, केंद्रीय पुलिस बलों, पुलिस एवं सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद जवान परवेज अहमद डार के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी।
- श्रीनगर में यूथ क्लब के सदस्यों से संवाद किया। सूफी संतों से भेंट कर शांति और सह अस्तित्व को पुनस्थार्पित करने के लिए व्यापक चर्चा की।
- श्रीनगर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया और जनसभा को संबोधित किया। सीआरपीएफ के कैंप में रात बिताई और जवानों को संबोधित किया। साथ ही पुलवामा के कायराना आंतकी हमले में शहीद हुए बहादुर जवानों को पुलवामा शहीद स्मारक पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की और वहां वीर बलिदानियों की स्मृति में पौधारोपण किया।

विकास को मिल रही है नई गति

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में 12 हजार करोड़ रुपए का निवेश आया है। 2022 तक 51 हजार करोड़ का निवेश आने वाला है।
- जल्द ही श्रीनगर में मेट्रो की शुरुआत होने वाली है और 700 करोड़ रुपए से जम्मू एयरपोर्ट का भी विकास होने वाला है।
- श्रीनगर में 115 करोड़ रुपए की लागत से 500 बिस्तर के अस्पताल का काम पूरा, हंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास, 4,000 करोड़ रुपये की सड़कें बनाने का काम भी शुरु।
- मार्च 2020 से मार्च 2021 के तक जम्मू-कश्मीर में 1.31 लाख पर्यटक आए, जो आजादी के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा है।
- नई हेलीकाप्टर पॉलिसी के तहत जम्मू कश्मीर के हर जिले में हैलीपैड बनाकर हर जिले को आपस में जोड़ने का भी काम शुरु किया गया है।
- श्रीनगर-शारजाह के बीच सीधी कनैक्टिविटी से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस उड़ान से 11 साल बाद श्रीनगर हवाई अड्डे को फिर से अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की पहचान मिलेगी।

अन्याय नहीं कर सकता। अब जम्मू और कश्मीर दोनों का विकास हो रहा है और अब संविधान से सभी अधिकार यहां के सभी लोगों को मिल रहे हैं और जम्मू कश्मीर शांति, स्थिरता, विकास व समृद्धि के मार्ग पर चलकर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बढ़-चढ़ कर अपना योगदान दे रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में बसे जम्मू कश्मीर में विकास के नए युग की शुरुआत संभव हुई और वहां के लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना उनकी प्राथमिकता बन गई है। ●

अब आपके सिर पर अपनी छत

घर की चाबी सम्मान, आत्मविश्वास, सुनिश्चित भविष्य, नई पहचान और बढ़ती संभावनाओं का द्वार खोलती है। अपने सपनों के घर की यह चाबी देश के हर गरीब और जरूरतमंद के पास हो, वो भी आजादी के 75 वर्ष पूरे होने तक अमृत महोत्सव में इससे बेहतर और क्या होगा? इसी सपने के साथ वर्ष 2015 में एक शुरुआत हुई प्रधानमंत्री आवास योजना की। 3 करोड़ से ज्यादा पक्के घरों के निर्माण के साथ सबको पक्का घर का सपना पूरा करने की ओर बढ़ रहे हैं कदम...

आगरा की विमलेश पहले कच्चे और टूटे हुए मकान में रहती थीं। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब उन्हें नया और पक्का घर मिल गया। विमलेश कहती हैं, "पहले घर पर रिश्तेदार आते थे तो शर्म लगती है। यह सोचना भी मुश्किल था कि कभी अपना पक्का घर होगा। लेकिन पीएम आवास योजना ने हमारा घर का सपना साकार कर दिया।"

उत्तर प्रदेश के ललितपुर में रहने वाली बबीता की कहानी भी कुछ विमलेश की तरह ही है। कच्चे मकान में बारिश के बीच टपकते पानी की वजह से जहां पहले खाना बनाना दूभर था और कीड़े-मकौड़ों के बीच जिंदगी मुश्किल, लेकिन अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले मकान के बाद बबीता के लिए वो दिन सिर्फ एक बुरी याद ही रह गए हैं।

जम्मू के बुआ दित्ता, कानपुर की रामजानकी पाल और ओडिशा के बलांगीर की 80 वर्षीय शशि बारिक भी पीएम आवास योजना के लाभार्थियों में शामिल हैं। शशि बताती हैं, "हम अब पक्के मकान

> **"मेरे जो साथी, झुग्गी-झोपड़ी में जिंदगी जीते थे, उनकी पास पक्की छत नहीं थी, ऐसे तीन करोड़ परिवारों को लखपति बनने का अवसर मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में जो करीब-करीब 3 करोड़ घर बने हैं, आप उनकी कीमत का अंदाजा लगाइए। ये लोग लखपति बने हैं।"**
>
> **- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

वो सब जो आपको जानना चाहिए...

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) यानी शहरी मध्यम वर्ग को राहतभरी सौगात

यह योजना 25 जून, 2015 को लांच की गई जिसे चार हिस्सों में बांटा गया है

01 इन सिटू रि-डेवलपमेंट(आईएसएसआर): इसमें प्रति घर एक लाख रुपए की सहायता राशि केंद्र सरकार देती है। प्राइवेट डेवलपर की मदद से स्लम बस्ती में रहने वालों का पुनर्वास करना।

02 कमजोर वर्ग को क्रेडिट लिंक सब्सिडी से अफॉर्डेबल हाउसिंग।

03 पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्शिप में हाउसिंग योजना की भी शुरुआत की गई है।

04 गरीब और आम लोगों को घर निर्माण के लिए सब्सिडी बढ़ाना।

कौन है योजना का पात्र

- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(ईडब्ल्यूएस): जिस परिवार की वार्षिक आय 3 लाख तक है। मकान साइज 30 वर्गमीटर।
- कम आय वर्ग(एलआईजी): ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 3-6 लाख रुपए है। मध्यम आय वर्ग(एमआईजी): ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 12 लाख रुपए से कम है। 2.35 लाख रुपए क्रेडिट लिंक स्कीम में सब्सिडी मिल सकती है।
- मध्यम आय वर्ग(एमआईजी)2: ऐसे व्यक्ति जिनकी सालाना आय 18 लाख रुपए से कम है। वो 2.35 लाख रुपए की क्रेडिट लिंक सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं।
- 30 वर्ग मीटर तक का मकान जिसमें पानी, सीवर और शौचालय की सुविधा शामिल हो। कम आय वर्ग(एलआईजी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(ईडब्ल्यूएस) से संबंध रखते हैं तो 1 लाख रुपए से 2.30 लाख रुपए ब्याज राशि में सब्सिडी मिलती है। अपने मकान के पुनर्निर्माण के लिए 1.5 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी।

आप ऐसे कर सकते हैं क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम में आवेदन

आप कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर आधार और फोटो के साथ 25 रुपए का शुल्क चुकाकर या खुद आधिकारिक वेबसाइट **https://pmaymis.gov.in/** पर लॉग इन करके आवेदन कर सकते हैं। आधार नंबर और नाम भरकर ना सिर्फ पात्रता का पता चल जाएगा बल्कि खुलने वाले पेज पर अपनी पूरी जानकारी देकर आवेदन कर सकते हैं।

सफलता की कहानी कहते आंकड़े

1.14 करोड़ घरों को मिली मंजूरी इस योजना में।

51.8 लाख से अधिक घर पूर हुए।

88.64 लाख घरों का निर्माण कार्य चल रहा है।

7.52 लाख करोड़ कुल निवेश।

113179 करोड़ रुपया केन्द्रीय सहायता जारी की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत।

आंकड़े- 29 अक्टूबर 2021 तक।

में रह रहे हैं। हमारे जैसे गरीब परिवारों को पक्का मकान बनाने में सहायता करने के लिए सरकार का धन्यवाद। अब हम इस मकान के खुद मालिक हैं।" गरीबों को अपना घर देने की कोशिशें तो देश में कई दशक से चल रही थीं। लेकिन हर 10-15 साल में इन योजनाओं में कुछ जुड़ता गया और नाम बदलते गए। नतीजा, थोपे गए नियम और पारदर्शिता की कमी के चलते लक्ष्य पूरा ही नहीं हो पाया। वर्ष 2014 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन योजनाओं पर सवाल भी उठाया गया। वहीं, दूसरी ओर लगातार बढ़ती आबादी और उसके साथ ही झुग्गी-झोंपड़ियों की बढ़ती संख्या के बीच एक बहुत बड़ा वर्ग जीवन-यापन की

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) यानी अब गरीब तक खुद पहुंची सरकार

- पीएमएवाई-जी में सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना 2011 के आधार पर बेघर, एक या दो कमरों की कच्ची दीवार या कच्ची छत के मकान में रहने वालों को प्राथमिकता के हिसाब से इसी क्रम में लाभ मिलेगा।
- मकान निर्माण के लिए मैदानी क्षेत्र में 1.20 लाख रुपए व पर्वतीय क्षेत्रों में 1.30 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
- आवेदन व सहायता के समय मकान के फोटो की जियो टैगिंग की जाएगी। मंजूरी के 7 दिन में मकान निर्माण की पहली किस्त आएगी। 12 महीने में निर्माण पूरा करना होता है।
- लाभार्थी के चयन से लेकर मकान निर्माण व लाभार्थी को घर देने तक की पूरी प्रक्रिया वैज्ञानिक व पारदर्शी है। पहले गरीब सरकार के चक्कर काटते थे, अब सरकार गरीब तक स्वयं पहुंचती है।
- निर्माण के प्रत्येक चरण पर पूरी निगरानी रखी जाती है। निर्माण जैसे-जैसे बढ़ता है, वैसे-वैसे सरकार सहायता राशि जारी करती है।

20891387	**220101.23**	**16202194**	**27271133**	**22007799**
करोड़ घरों को मंजूरी।	करोड़ केन्द्रीय सहायता।	से अधिक घर पूरे।	घरों का लक्ष्य।	रजिस्टर्ड।

आंकड़े- 29 अक्टूबर 2021 तक।

अफॉर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम (एआरएचएस) की शुरुआत

प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी के तहत किफायती किराए की योजना की शुरुआत भी की गई है। इसमें 30 वर्ग मीटर तक के एक बेडरूम सेट, 10 वर्ग मीटर तक के डोरमेट्री और एलआईजी 60 वर्ग मीटर तक के दो बेडरूम का सेट सरकार के खाली मकान या पीपीपी मॉडल में प्राइवेट डेवलपर उपलब्ध कराएंगे। प्रवासी मजदूरों को कार्यस्थल के नजदीक ऐसे किराए के मकान मार्च, 2022 से उपलब्ध कराने का लक्ष्य दिया गया है। किराया लोकल मार्केट सर्वे के आधार पर शहरी स्थानीय निकाय और संचालक या संस्थाएं खुद तय करेंगी।

सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास के साथ सबका प्रयास का अनुपम उदाहरण

- घर केवल चारदीवार और छत से ही नहीं बनता। इसके लिए और भी जरूरतें होती हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना को केंद्र सरकार की दूसरी योजनाओं से भी जोड़ा गया है। जैसे- आवास तभी पूरा होगा, जब इसमें शौचालय का निर्माण हो जाएगा। इसके लिए स्वच्छता मिशन के तहत राशि उपलब्ध कराई जाती है।
- मनरेगा के तहत 90/95 श्रम दिवस की अकुशल मजदूरी का प्रावधान है। यह राशि करीब 18,000 रुपये होती है।
- दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति व उजाला योजना के तहत बिजली के कनेक्शन, उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर की सुविधा और जल जीवन मिशन के जरिए पानी के लिए नल कनेक्शन भी दिया जा रहा है।
- इस योजना की कुल लागत का बंटवारा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच 60:40 के अनुपात में किया जाता है, जबकि पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों के लिये यह राशि 90:10 के अनुपात में साझा की जाती है। अच्छे गुणवत्ता के मकानों के निर्माण के लिए पूरे भारत में राज मिस्त्रियों के प्रशिक्षण और प्रमाणन की व्यवस्था की गई।

महिला सशक्तीकरण की राह आसान

विधवा, अविवाहित और जीवनसाथी से अलग रहने के मामलों को छोड़ कर संयुक्त रूप से पति और पत्नी, दोनों के नाम पर घर किया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 31 मार्च 2021 तक कुल आवास में से 68 फीसदी एकल या फिर संयुक्त रूप से ग्रामीण महिलाओं के नाम से स्वीकृत किए गए हैं।

सबसे मूलभूत जरूरतों में से एक 'आवास' के लिए मोहताज था।

इसीलिए 25 जून 2015 को बिलकुल नए स्वरूप के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना लाई गई। पहले शुरुआत हुई प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी की और फिर आई प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। लक्ष्य निर्धारित किया गया- वर्ष 2022 तक ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 2.95 करोड़ और शहरी क्षेत्र में करीब 1.12 करोड़ घरों का निर्माण। इतने कम समय में तय लक्ष्य एक चुनौती ही थी, लेकिन ऐसी चुनौतियों को स्वीकार कर तय समय में लक्ष्यों को पूरा करना ही आज केंद्र सरकार की प्राथमिक और जनता के प्रति जवादेही की निशानी है।

कैबिनेट के फैसले

राष्ट्र की प्रगति को मिली 'गति' की 'शक्ति'

योजना बनाना या उसका शुभारंभ करना ही नहीं, बल्कि उसे तत्काल जमीन पर उतारने की प्रक्रिया पर तेजी से काम करना, वर्तमान केंद्र सरकार की नीतियों का आधार है। यही वजह है कि 13 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम-गतिशक्ति जैसी महायोजना का शुभारंभ किया और सप्ताह भर के भीतर ही 21 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी देकर क्रियान्वयन का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया। पीएम-गतिशक्ति विकास योजना के प्रति केंद्र सरकार के दृष्टिकोण में एक सार्थक व महत्त्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गतिशक्ति समग्र सुशासन सुनिश्चित करेगी, जिसके केंद्र में हैं भारत के लोग, भारत के उद्योग, भारत के निर्माता और भारत के किसान

फैसला: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) को मंजूरी दी; महायोजना के कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त हुआ।

- प्रभाव: प्रधानमंत्री ने 13 अक्टूबर, 2021 को मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गतिशक्ति एनएमपी का शुभारंभ किया। जिसे सप्ताह भर के भीतर कैबिनेट की मंजूरी से क्रियान्वयन की राह आगे बढ़ी।
- इससे नेक्सटजेन इंफ्रा को जबरदस्त प्रोत्साहन मिलेगा। पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की तीन स्तरीय प्रणाली में होगी निगरानी।
- इंफ्रास्ट्रक्चर सभी परियोजनाओं को निर्बाध रूप से एकीकृत करेगा और बाधाओं को दूर करेगा।
- संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित कर दक्षता और आर्थिक लाभ को बढ़ावा।
- 18 मंत्रालयों के सचिव मल्टीमॉडल नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप का गठन करेंगे। पीएम गतिशक्ति एनएमपी की निगरानी त्रिस्तरीय प्रणाली में की जाएगी। इसमें सबसे ऊपर कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों का एक अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएस) होगा।
- पीएम गतिशक्ति एनएमपी का उद्देश्य मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और लास्ट माइल कनेक्टिविटी की समस्याओं को हल करने के लिए विभागीय दायरों को तोड़ना और परियोजनाओं की अधिक समग्र और एकीकृत योजना बनाकर उसे क्रियान्वित करना है।
- इससे लॉजिस्टिक लागत को कम करने में मदद मिलेगी। इससे उपभोक्ताओं, किसानों, युवाओं के साथ-साथ व्यवसायों में लगे लोगों को अधिक आर्थिक लाभ होगा।
- यह महायोजना संसाधनों और क्षमताओं का अधिकतम उपयोग, दक्षता बढ़ाने और अपव्यय को कम करना सुनिश्चित करेगी।
- इस मंजूरी के साथ, पीएम गतिशक्ति की शुरुआत को और गति मिलेगी जिसके परिणामस्वरूप देश में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए समग्र और एकीकृत योजना ढांचा तैयार होगा।

फैसला: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 01.07.2021 से देय केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दी।

- प्रभाव: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त जारी और पेंशनरों को महंगाई राहत मिलेगी।
- मूल वेतन/पेंशन की मौजूदा दर 28% से 3% की वृद्धि। अतिरिक्त किस्त 1 जुलाई 2021 से प्रभावी होगी। 47.14 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 68.62 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।

67 वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के अवार्ड

रजनीकांत ने किया दोस्त और ड्राइवर को याद

उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडु ने ने जब जाने-माने अभिनेता और दक्षिण भारतीय फिल्म में भगवान का दर्जा रखने वाले रजनीकांत को दादासाहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया तो वहां मौजूद सभी लोगों ने खड़े होकर तालियां बजा कर उनका स्वागत किया। इस उपलब्धि के लिए उन्होंने फैंस को धन्यवाद कहा और यह सम्मान अपने गुरु, मेंटर और जाने-माने के बालाचंदर को समर्पित किया।

नई दिल्ली के विज्ञान भवन में उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडु ने प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार सहित वर्ष 2019 के लिए विभिन्न श्रेणियों में घोषित 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 25 अक्टूबर 2021 को प्रदान किए। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की ज्यूरी ने 2019 के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा 22 मार्च 2021 को की थी...

मनोज वाजपेयी और धनुष को बेस्ट ऐक्टर का सम्मान

फिल्म 'भोंसले' में यादगार भूमिका के लिए अभिनेता मनोज वाजपेयी को बेस्ट एक्टर का सम्मान दिया गया। यह सम्मान उन्हें संयुक्त रूप से अभिनेता धनुष के साथ दिया गया। फिल्म असुरन के लिए रजनीकांत के दामाद और अभिनेता धनुष को बेस्ट ऐक्टर का सम्मान मिला।

बी. प्राक - हिन्दी फिल्म 'केसरी' के गाने तेरी मिट्टी गीत के लिए बी. प्राक को बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल और सिवानी रवींद्र को 'बार्दो' फिल्म के गाने के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल का सम्मान दिया गया।

बेस्ट फिल्म- हिन्दी में सुशांत सिंह राजपूत स्टारर छिछोरे, तमिल में असुरन, मराठी में बार्दो को बेस्ट मराठी फिल्म का सम्मान दिया गया।

विजय सेतुपति- विजय सेतुपति को तमिल फिल्म 'सुपर डीलक्स' के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का खिताब दिया गया।

पल्लवी जोशी - 'ताशकंद फाइल्स' में अभिनय के लिए पल्लवी जोशी को बेस्ट सपोर्टिंग अभिनेत्री का सम्मान दिया गया।

कंगना को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार

मणिकर्णिका- दि क्वीन ऑफ झांसी और पंगा जैसी फिल्मों में अभिनय का जलवा बिखेरने के लिए कंगना रनौत को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। कंगना पारंपरिक भारतीय साड़ी में पुरस्कार लेने मंच पर पहुंची और उसके खाते में यह चौथा राष्ट्रीय पुरस्कार है।

PMO India @PMOIndia

आज केंद्र और राज्य में वो सरकार है जो गरीब, दलित, शोषित-वंचित, पिछड़े, मध्यम वर्ग, सभी का दर्द समझती है।

देश में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने के लिए हम दिन रात एक कर रहे हैं: PM @narendramodi

Rajnath Singh @rajnathsingh

The DefExpo-2022 will be held at Gandhinagar in Gujarat, from 10th to 13th March 2022.

DefExpo-2022 is going to be one of the marquee events to mark the #AzadiKaAmritMahotsav.

Amit Shah @AmitShah ·

देश हित में धारा 370 हटने के बाद घाटी में हिंसा की अटकलें लगाई जाती थी, लेकिन CRPF की मुस्तैदी के कारण कहीं पर किसी को एक गोली भी नहीं चलानी पड़ी ये हम सभी के लिए बहुत गर्व का विषय है।

आपकी मुस्तैदी के कारण ही बिना रक्तपात के आज जम्मू-कश्मीर में विकास के नए युग की शुरुआत हुई है।

Nitin Gadkari @nitin_gadkari

MoRTH has issued new safety guidelines for children below 4 years of age being carried on a motorcycle. A safety harness shall be provided to attach the child to the driver of the motorcycle.

Child pillion passengers aged between 9 months to 4 years must wear crash helmets. The speed of the motorcycle with the child up to age 4 years shall not be more than 40 kmph.

Dr Mansukh Mandavi...

ना हम रुके कहीं, ना हम डिगे कहीं
शत्रु हो कोई भी हम झुके नहीं

दुश्मन के शस्त्र जो हो हज़ार
शत कोटि कवच से हम तैयार

मेरे भारत का ये विश्वास है
सबका साथ, सबका प्रयास है।

भारत का टीकाकरण लिख रहा एक नया इतिहास है....

Bhupender Yadav @byadav...

Happy to inform that the @LabourMinistry has revised minimum wages (variable dearness allowance) applicable for scheduled employment in the central sphere. The hike, which will be effective from October 1, will benefit about 1.5 crore workers.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान-भारत समिट में की शिरकत

दक्षिण चीन सागर में शांति, स्थिरता, सुरक्षा और आतंकवाद समेत क्षेत्रीय मुद्दे उठाए

हरिभूमि ब्यूरो ▶▶| नई दिल्ली

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 2022 में भारत और आसियान की साझेदारी को 30 साल पूरे हो जाएंगे और इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को आसियान-भारत मित्रता वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आसियान की एकता और केंद्रीयता भारत के लिए सदैव महत्वपूर्ण।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को 18वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के दौरान इंडिया-आसियान संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। आसियान देशों की यही मित्रता भविष्य में संबंधों को मजबूत बनाए रखेगी और लोगों के बीच सद्भावना का आधार बनेगी। कोविड के कारण सभी को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यह चुनौतीपूर्ण समय भारत-आसियान मित्रता की परीक्षा की घड़ी भी थी। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और आसियान के बीच हजारों वर्षों के जीवंत संबंध का इतिहास रहा है। इसकी झलक हमारे साझा मूल्य, परंपराएं, भाषाएं, ग्रंथ, वास्तुकला, संस्कृति और खान-पान में साफ देखने को मिलती है। आसियान की एकता हमेशा से भारत की प्राथमिकता रही है। वर्ष 2022 में भारत-आसियान साझेदारी के 30 साल पूरे होंगे और भारत भी अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा करेगा। इसे भारत आसियान-भारत

खास बातें

- डिजिटल तरीके से होने वाले इस सम्मेलन में आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्ष/शासनाध्यक्ष ने भाग लिया
- कारोबार एवं निवेश, कोविड महामारी के बाद आर्थिक सुधार व विविधतापूर्ण महत्व को रेखांकित किया

हर साल आयोजित किया जाता आसियान भारत शिखर सम्मेलन

आसियान-भारत शिखर सम्मेलन हर साल आयोजित किया जाता है और यह भारत और आसियान को उच्चतम स्तर पर जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल नवंबर में 17वें आसियान सम्मेलन में हिस्सा लिया था। इस बार उन्होंने 9वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। 2005 में अपनी स्थापना के बाद

आह्वान : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा, खरीदारी का मतलब वोकल फॉर लोकल है

स्थानीय उत्पाद खरीद गरीब का घर रोशन करें

नई दिल्ली | विशेष संवाददाता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्व और त्योहारों के मद्देनजर रविवार को देशवासियों से स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की। उन्होंने कहा कि खरीदारी मतलब 'वोकल फॉर लोकल' है। आप स्थानीय उत्पाद खरीदेंगे तो किसी गरीब भाई-बहन, कारीगर, बुनकर के घर में भी रोशनी आएगी।

टीकाकरण अभियान से नई ऊर्जा का संचार: आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 82वीं कड़ी में देशवासियों से बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में सौ करोड़ कोरोना टीकाकरण से नया उत्साह और नई ऊर्जा का संचार हुआ है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण की सफलता में राष्ट्र के सामर्थ्य और सबके प्रयास के मंत्र की शक्ति दिखाई देती है।

कई अनुभव और उदाहरण: प्रधानमंत्री ने कहा कि सौ करोड़ कोरोना टीके का आंकड़ा बहुत बड़ा जरूर है, पर इसमें लाखों छोटी-छोटी प्रेरक और गर्व से भर देने वाले अनेक अनुभव और उदाहरण जुड़े हैं। इसके लिए उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों के परिश्रम और संकल्प की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत के टीकाकरण कार्यक्रम की सफलता को लेकर वह आश्वस्त थे। क्योंकि, वह देशवासियों की क्षमताओं से भलीभांति परिचित हैं।

"लोग अपने यहां के स्थानीय उत्पाद खरीदें। मुझे पूरा भरोसा है जो मुहिम हम सबने मिलकर शुरू की है, इस बार त्योहारों में और भी मजबूत होगी। -नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

उत्तराखंड : महिला स्वास्थ्यकर्मी से बात की

प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर उत्तराखंड के बागेश्वर की एक महिला स्वास्थ्यकर्मी पूनम नौटियाल से बात की। उन्होंने नौटियाल से कहा, 'आज मैं सिर्फ आपका ही आभार व्यक्त नहीं कर रहा हूं बल्कि हर उस भारतवासी का आभार व्यक्त कर रहा हूं, जिसने 'सबको टीके-मुफ्त टीके' अभियान को कामयाबी दी।

यूपी : ग्रेटर नोएडा के रामवीर की तारीफ

प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रेटर नोएडा के डाढ़ा गांव के रहने वाले रामवीर तंवर का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग उन्हें पांड मैन के नाम से बुलाते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छता तभी बरकरार रह सकेगी जब इस तरह से लोग काम करेंगे। मोदी ने कहा कि रामवीर अब तक 40 तालाबों की सफाई करा चुके हैं।

झारखंड : बिरसा मुंडा से सीख लें

बिरसा मुंडा का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश अगले महीने उनकी जयंती मनाएगा। उनके जीवन से हमें कई अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। मसलन, हमें अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। बिरसा मुंडा ने भी अपनी संस्कृति, अपने जंगल और अपनी जमीन की रक्षा के लिए संघर्ष किया था। उन्होंने सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए समाज को जागरूक भी किया।

महिला पुलिसकर्मियों की संख्या दोगुनी से ज्यादा: प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले यह धारणा बन गई थी कि सेना और पुलिस जैसी सेवा केवल पुरुषों के लिए ही होती है। लेकिन आज ऐसा नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या दोगुनी हुई है। 2014 में इनकी संख्या 1.5 लाख के करीब थी, वहीं वर्ष 2020 तक इसमें दोगुने से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। यह संख्या 2.15 लाख तक पहुंच गई है।

82 वां संस्करण था मन की बात कार्यक्रम का

02 गुना से अधिक हुईं महिला पुलिसकर्मी

अपील

एकता का संदेश देने वाली गतिविधि से जरूर जुड़ें

आगामी 31 अक्तूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाए जाने वाले 'राष्ट्रीय एकता दिवस' का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सभी का दायित्व है कि वह एकता का संदेश देने वाली किसी-न-किसी गतिविधि से जरूर जुड़ें।

बेटियों पर नाज

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश की बेटियां कठिन से कठिन कर्तव्य भी पूरी ताकत और हौसले से पूरा कर रही हैं। आगे जाकर बेटियां कोबरा बटालियन का हिस्सा बनेंगी।

प्रधानमंत्री ने कहा, सभी देशों की क्षेत्रीय एकता के लिए प्रतिबद्ध

खुला हिंद-प्रशांत क्षेत्र भारत के लिए महत्वपूर्ण : मोदी

संबोधन

नई दिल्ली | एजेंसी

नई दिल्ली में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये 16वें पूर्वी-एशिया शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। • एपी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को एक बार फिर इस बात की तस्दीक की कि एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान की केंद्रीयता का समर्थन भारत के व्यापक दृष्टिकोण के मूल केंद्र में है। प्रधानमंत्री ने 16वें पूर्वी-एशिया शिखर सम्मेलन में भी डिजिटल माध्यम से हिस्सा लेते हुए यह बात कही। इस सम्मेलन की मेजबानी ब्रुनेई के सुल्तान हसनल बोलकिया कर रहे थे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत बहुपक्षीयवाद के साझा मूल्यों के प्रति सम्मान, नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय

माध्यम से शामिल हुआ। एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान की केंद्रीयता का समर्थन भारत के व्यापक दृष्टिकोण के

साझेदारी, कोरोना व स्वास्थ्य, व्यापार, शिक्षा व संपर्क सहित अन्य प्रमुख क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी। डिजिटल माध्यम से होने वाले इस सम्मेलन में आसियान देशों के

100 करोड़ डोज के बाद देश में नई ऊर्जा: मोदी

■ पीटीआई, नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि अपने नागरिकों को 100 करोड़ वैक्सीन डोज देना भारत के सामर्थ्य और 'सबके प्रयास' के मंत्र की शक्ति को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि उपलब्धि के बाद देश नए उत्साह और नई ऊर्जा से आगे बढ़ रहा है। 'मन की बात' कार्यक्रम में मोदी ने कहा, 'मैं जानता था कि हमारे स्वास्थ्यकर्मी देशवासियों के टीकाकरण में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेंगे।' उन्होंने कहा, 'हमारे स्वास्थ्य-कर्मियों ने अपने अथक परिश्रम और संकल्प से एक नई मिसाल पेश की है।' पीएम ने उत्तराखंड के बागेश्वर की एक महिला स्वास्थ्यकर्मी पूनम नौटियाल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं जानता था कि हेल्थ वर्कर्स कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

से बात की। उन्होंने नौटियाल से कहा, 'आज मैं सिर्फ आपका ही आभार व्यक्त नहीं कर रहा हूं बल्कि हर उस भारतवासी का आभार व्यक्त कर रहा हूं, जिसने 'सबको टीके-मुफ्त टीके' अभियान को कामयाबी दी।'

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत परिवहन के लिए ड्रोन का उपयोग करने पर काम कर रहा है, जिसमें घरों में सामान की डिलिवरी और आपात स्थिति के दौरान सहायता और कानून व्यवस्था की निगरानी शामिल है। उन्होंने कहा कि जल्द ही ऐसी सभी जरूरतों के लिए ड्रोन तैनात किए जाएंगे। मोदी ने कहा कि नई ड्रोन नीति इस नीति के लागू होने के बाद कई विदेशी और घरेलू स्टार्टअप ने ड्रोन स्टार्टअप्स में निवेश किया है। सेना, नौसेना और वायु सेना ने ड्रोन के लिए भारतीय कंपनियों को 500 करोड़ रुपये से अधिक का ऑर्डर दिया है।

PM ने 64 हजार क..ड़ की स्वास्थ्य योजना शुरू की

■ एनबीटी ब्यूरो, वाराणसी

पीएम मोदी ने सोमवार को वाराणसी से प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत की। पीएम ने कहा कि 64,000 करोड़ रुपये की लागत वाली यह योजना स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को आत्मनिर्भर बनाएगी। उन्होंने कहा, 'आजादी के बाद लंबे समय तक रही सरकारों ने हेल्थ केयर सिस्टम पर ध्यान न देकर जनता को स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रखा। आने वाले चार-पांच सालों में गांव, ब्लॉक, जिला तक क्रिटिकल केयर यूनिट को सशक्त किया जाएगा। वेलनेस सेंटर खुलने से समय से बीमारियों का पता चलेगा, तो इलाज में आसानी होगी। राष्ट्रीय स्तर पर 12 केंद्रीय अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। 24 घंटे चलने वाले इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर तैयार किए जाएंगे।'

10 लाख तक का फ्री इलाज देंगे : प्रियंका

कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने सोमवार को एक और ऐलान किया। उन्होंने ट्वीट किया कि यूपी में कांग्रेस की सरकार बनी तो 10 लाख रुपये तक का इलाज फ्री होगा। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी इसे अपने घोषणापत्र में भी लाएगी।

आर.एन.आई
DELHIN/2020/78812
16-30 नवंबर 2021

न्यू इंडिया
समाचार
पाक्षिक

आरएनआई DELHIN/2020/78812, दिल्ली पोस्टल लाइसेंस नंबर -
DL (S)-1/3550/2020-22 डब्ल्यूपीपी संख्या U (S)-98/2020-22, posting at BPC,
Meghdoot Bhawan, New Delhi - 110 001 on 13-17 advance Fortnightly
(प्रकाशन तिथि - 03 नवंबर 2021, कुल पृष्ठ-44)

आज़ादी का अमृत महोत्सव

लक्ष्य विशाल उपलब्धि बेमिसाल

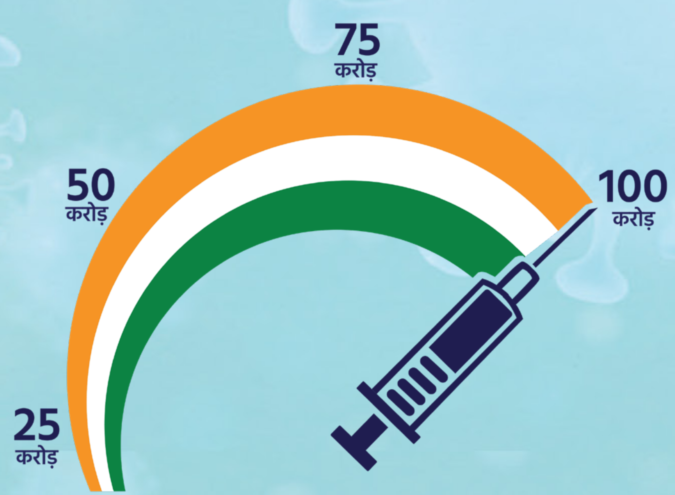

भारत द्वारा 100 करोड़ टीकाकरण का सफ़र

सबका साथ सबका प्रयास | **जन सामर्थ्य से देश रच रहा इतिहास**

> "100 करोड़ वैक्सीन डोज, ये केवल एक आंकड़ा नहीं है। ये देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है, इतिहास के नए अध्याय की रचना है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो कठिन लक्ष्य निर्धारित कर, उन्हें हासिल करना जानता है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो अपने संकल्पों की सिद्धि के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करता है।"

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

संपादक:
जयदीप भटनागर, प्रधान महानिदेशक, पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली

प्रकाशक और मुद्रक:
सत्येन्द्र प्रकाश, प्रधान महानिदेशक, बीओसी (ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन)

कमरा संख्या-278, ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन, सूचना भवन, द्वितीय तल, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित

मुद्रण: जेके ऑफसेट ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड, बी-278, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020